वर्ष : 34 | अंक : 378 | मुंबई, शुक्रवार, 27 मार्च 2026 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

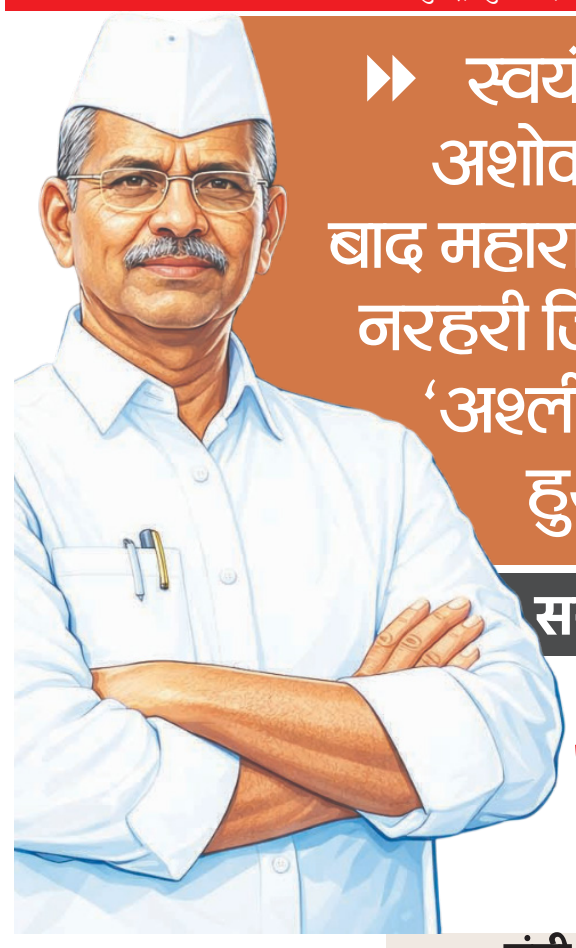

स्वयंभू गॉडमैन अशोक खरात के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नरहरी जिरवाल का 'अश्लील' वीडियो हुआ वायरल

सरकारी बंगले से आश्रम तक अय्याशी और ब्लैकमेलिंग का खेल

डर्टी पॉलिटिक्स

डीबीडी संवाददाता । मुंबई/नासिक

स वक्त 'अश्लील वीडियो' के एक ऐसे दोहरे चक्रवात में फंसी है, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर संतों के आश्रमों तक की शुचिता पर कालिख पोत दी है। नासिक के स्वयंभू 'गॉडमैन' अशोक खरात के 'वीडियो कांड' से मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है।

मंत्री जिरवाल से विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि मंत्री जिरवाल सरकारी आवास पर किन्नर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने अब इसी वीडियो को आधार बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

विपक्ष ने क्या कहा?

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की गौरवशाली राजनीति के नैतिक पतन का प्रमाण है। जनता के टैक्स के पैसे पर पलने वाले और जिम्मेदार पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के अनैतिक व्यवहार में शामिल होंगे, तो समाज में क्या संदेश जाएगा?

ब्लैकमेलिंग या राजनीतिक साजिश?

वहीं, विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर उस ट्रांसजेंडर के भाई ने इस वीडियो को वायरल किया है, जिससे मंत्री को ब्लैकमेल किया जा सके। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कहा कि सरकारी आवास में इस तरह की गतिविधियां मर्यादा के खिलाफ हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।

मुश्किलों में घिरे जिरवाल

नरहरि जिरवाल के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले महीने ही उनके कार्यालय के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। जिसके बाद उन्हें अपने निजी सचिव को पद से हटाना पड़ा था। अब इस नए कांड ने उनकी कुर्सी पर खतरा और बढ़ा दिया है। हालांकि, इस पूरे विवाद पर अभी तक मंत्री जिरवाल या उनकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

अशोक खरात केस में बड़े खुलासे

100 अश्लील वीडियो, 1500 करोड़ की संपत्ति और सरकार से मिले 1 करोड़

नासिक। नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय स्कैंडल बन चुका है। 2018 में सरकारी फंड मिलने के खुलासे ने इस 'ढोंगी साम्राज्य' की जड़ों को शासन-प्रशासन तक फैला हुआ दिखाया है। आधिकारिक दस्तावेजों से पता चला है कि 31 मार्च 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने सिन्नर स्थित 'श्री इशान्येश्वर देवस्थान ट्रस्ट' के लिए 1.05 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उस समय बीजेपी नेता जयकुमार रावल पर्यटन मंत्री थे। इस फंड का इस्तेमाल मंदिर में हॉल, पार्किंग, गार्डन और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था के लिए किया जाना था। 25 लाख रुपये की पहली किस्त PWD के जरिए खर्च भी कर दी गई थी।

रसूख और राजनीतिक पहुंच

जांच में यह बात सामने आई है कि अशोक खरात के दरबार में बड़े-बड़े राजनेताओं का आना-जाना था। इसी रसूख का फायदा उठाकर उसने सरकारी योजनाओं के तहत अपने ट्रस्ट को सबसे ज्यादा फंड दिलवाया। उस समय खरात के खिलाफ कोई केस नहीं था, इसलिए उसे 'क्लीन चिट' मानकर फंड दिया गया, लेकिन अब यही फंडिंग सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। आईपीएस तेजस्वी सातपुते की SIT को जांच के दौरान खरात के ठिकानों से 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। साइबर पुलिस जांच कर रही है कि क्या इनका इस्तेमाल वीआईपी लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया?

चंदे से चांदी

- सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 6648.563 करोड़ रुपये का चंदा मिला
- कांग्रेस समेत चार राष्ट्रीय दलों के कुल चंदे से 1000% ज्यादा बीजेपी को मिला

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

वित्त वर्ष 2024-25 में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की चंदे से हुई कमाई के आंकड़े सामने आ चुके हैं। भाजपा एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी के तौर पर उभरी है। वहीं, दूसरा नंबर कांग्रेस का है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के पहले नंबर के राजनीतिक दल और दूसरे नंबर के राजनीतिक दल के तरफ से जुटाए गए चंदे के बीच का दायरा करीब 12 गुना से ज्यादा है। यह आंकड़ा इसलिए भी आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि भाजपा के पास कांग्रेस के मुकाबले सिर्फ दोगुने दानकर्ता ही हैं। यानी साफ तौर पर भाजपा को मिलने वाला चंदा बड़ी राशियों का है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई और पार्टियों ने भी 2024-25 में मिले दान की राशि का खुलासा किया है।

अलग-अलग पार्टियों को कितना चंदा मिला?

सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर 11,343 दानकर्ताओं की तरफ से 6648.563 करोड़ रुपये का चंदा मिला। देशभर में राजनीतिक दलों को जितना चंदा मिला, उसकी कुल राशि में 91 फीसदी से ज्यादा भाजपा को ही मिली। भाजपा ने 2024-25 के लिए 6074.015 करोड़ रुपये का दान दिखाया है। उसे यह दान 5522 दानदाताओं के जरिए मिला। यह राशि भाजपा के बाद चंदा जुटाने वाले चार राष्ट्रीय दलों को मिले कुल चंदे से 10 गुना से भी अधिक है।

कांग्रेस ने अपना दान 517.394 करोड़ रुपये दिखाया है, जो कि उसे 2501 दानकर्ताओं से मिला है। कांग्रेस को मिली यह राशि भाजपा के मुकाबले करीब 1000 प्रतिशत कम है। आप ने 2024-25 के लिए अपनी दान की राशि 38.106 करोड़ रुपये दर्शायी है, जो कि उसे 2554 दानकर्ताओं की तरफ से मिली ।माकपा को 2024-25 में 16.957 करोड़ रुपये का दान मिला, जो कि 741 दानदाताओं से जुटाया गया। पूर्वोत्तर की इस प्रमुख पार्टी ने अपना दान 2.091 करोड़ रुपये दिखाया है, जो कि उसे 25 दानकर्ताओं से मिला। जिन दलों को चंदा मिला है, उनमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का है। पार्टी ने पिछले 19 साल की तरह इस बार भी यही दर्शाया है कि पार्टी को 20,000 रुपये से अधिक का कोई चंदा प्राप्त नहीं हुआ है। चुनाव आयोग को दिए गए आंकड़े में पार्टी ने 20 हजार रुपये से ज्यादा के दान को शून्य दिखाया है।

क्या रहे कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दान के आंकड़े?

राष्ट्रीय पार्टियों के चंदे का एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट दान से आता है। 2024-25 के आंकड़ों को देखा जाए तो सामने आता है कि इस बार भी कुल दान में से कॉरपोरेट दान का हिस्सा 92.18 फीसदी रहा है। राष्ट्रीय दलों को 3,244 कॉर्पोरेट या व्यापारिक घरानों से कुल 6128.787 करोड़ रुपये का दान मिला। 7,900 व्यक्तिगत दानदाताओं ने राष्ट्रीय दलों को कुल 505.66 करोड़ रुपये का दान दिया है।

चंदा देने में कौन सा राज्य कितना आगे?

राष्ट्रीय दलों को सबसे अधिक चंदा देने के मामले में राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। यहां से पार्टियों को 2639.48 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया। वहीं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां से राजनीतिक दलों को 2438.86 करोड़ रुपये का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर गुजरात रहा, जहां से पार्टियों को 309.17 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। भाजपा को 2,794 कॉरपोरेट दानकर्ताओं से सबसे ज्यादा 5717.167 करोड़ रुपये और 2,627 व्यक्तिगत दानदाताओं से 345.94 करोड़ रुपये का दान मिला। भाजपा की तरफ से जितना कॉरपोरेट चंदा घोषित किया गया है!

खेत-सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं

- 5 साल के लिए ब्लॉक होगा आधार और किसान कार्ड
- राजस्व मंत्री बावनकुले का बड़ा एलान

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और किसानों के बीच सड़क विवादों को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद सख्त और क्रांतिकारी कदम उठाया है। 26 मार्च 2026 को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ₹मुख्यमंत्री बलिराजा फार्म/पनंद रोड स्कीम₹ के तहत नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें अतिक्रमण करने वालों के सरकारी लाभ रोकने तक का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति गांव के नक्शे पर मौजूद सड़क, पनंद रास्ते या सरकारी जमीन पर कब्जा करता है या सड़क को नुकसान पहुँचाता है, तो उसका आधार कार्ड और किसान पहचान पत्र 5 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति 5 साल तक किसी भी सरकारी सब्सिडी, कर्ज या पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएगा।

7 दिन का फाइनल नोटिस

राजस्व विभाग के नए आदेश के अनुसार, यदि गांव के नक्शे वाली सड़क पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो तहसीलदार संबंधित व्यक्ति को 7 दिन का नोटिस देंगे। अगर इस दौरान कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन खुद बल प्रयोग कर उसे हटाएगा। उन रास्तों पर कोई फसल नहीं उगा पाएगा जहां किसानों को कानूनन आने-जाने का अधिकार मिला हुआ है।

जमीन दान पर बड़ी राहत

इस योजना के लिए सरकार कोई जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं करेगी। जो किसान अपनी मर्जी से सड़क के लिए जमीन दान करेंगे, उनके लिए सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी है। हालांकि, एक बार 'रिलीज़ डीड' या दान पत्र साइन होने के बाद किसान उस जमीन को वापस नहीं मांग सकेगा।

विधायकों को मिला नया अधिकार

विधानसभा क्षेत्र स्तर की कमेटियों में अब स्थानीय विधायकों का दबदबा रहेगा। पहले 5 प्रगतिशील किसानों को चुनने का तरीका अलग था, लेकिन अब स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र से किन्हीं भी 5 किसानों को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर सड़क विवादों को सुलझाने में तेज़ी आने की उम्मीद है।

ब्रीफ न्यूज़

प्रदेश में लाभार्थी परिवारों को मिल सकेगा 3 लीटर केरोसिन

मुंबई। खाड़ी देशों में जारी युद्ध के संकट और एलपीजी की संभावित किल्लत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पात्र परिवारों को सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से 3 लीटर केरोसिन वितरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, अंत्योदय (AAY) और प्राथमिकता परिवार (PHH) योजना के कार्ड धारकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

अब अनुभवी अधिकारियों को ही मिलेगी लोकल क्राइम ब्रांच में तैनाती

मुंबई। हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच की गुणवत्ता और पुलिस विभाग की छवि को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) में नियुक्तियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेशानुसार, अब क्राइम ब्रांच में केवल उन्हीं अधिकारियों की तैनाती की जाएगी ।

महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अब पार्टी पद पर भी संकट

मुंबई। महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अब रुपाली चाकणकर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि राकांपा (अजित) के भीतर ही उन्हें पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की और पार्टी की छवि को बचाने के लिए उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी से मुक्त करने का सुझाव दिया।

अवैध घुसपैठियों पर प्रशासन का एक्शन

भोईवाड़ा में खुला प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

भोईवाड़ा इलाके में महाराष्ट्र के पहले आधिकारिक डिटेंशन सेंटर (स्थानबद्धता केंद्र) का आगाज़ हो गया है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए गृह विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। 20 मार्च 2026 से शुरू हुआ यह केंद्र अब 'निर्वासन' (De-portation) की कानूनी प्रक्रिया का मुख्य अड्डा बनेगा। साल 2025-26 के दौरान मुंबई पुलिस ने एक सघन तलाशी अभियान चलाकर करीब 2500 से अधिक अवैध प्रवासियों (मुख्य रूप से बांग्लादेशी नागरिकों) को पकड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सामान्य जेलों में रखना सुरक्षा और कानूनी कारणों से मुश्किल हो रहा था। इसीलिए एक समर्पित सेंटर की मांग लंबे समय से थी, जिसे अब पूरा किया गया है।

150 लोगों की क्षमता और आधुनिक व्यवस्था

भोईवाड़ा का यह सेंटर अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ एक साथ 150 लोगों को रखा जा सकता है। खास बात यह है कि पुरुषों के अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए बिल्कुल अलग और सुरक्षित ब्लॉक तैयार किए गए हैं। शुरुआती चरण में 10 से 15 लोगों को यहाँ शिफ्ट भी कर दिया गया है।

यह कोई सामान्य जेल नहीं है। यहाँ उन विदेशी नागरिकों को रखा जाता है जिनकी पहचान हो चुकी है और अब उन्हें उनके मूल देश भेजने की कानूनी कागज़ी कार्रवाई चल रही है। जब तक उनके देश का दूतावास 'ट्रैवल परमिट' जारी नहीं करता, तब तक वे यहाँ पुलिस की सुरक्षित निगरानी में रहेंगे।इस केंद्र के शुरू होने से विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) और जाँच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बैठेगा।

रिलायंस टेलीकॉम पर सीबीआई का शिकंजा

114.98 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई में छापेमारी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में मुंबई में छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत पर दर्ज नई FIR के बाद की गई, जिसमें बैंक को करीब 114.98 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

CBI की टीमों ने मुंबई स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ पूर्व निदेशकों सतीश सेठ और गौतम बी. दोषी के आवासों पर भी तलाशी ली। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में ऋण लेनदेन, वित्तीय रिकॉर्ड और आंतरिक पत्राचार से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

735 करोड़ के लोन में गड़बड़ी का आरोप

SBI की शिकायत के अनुसार, रिलायंस टेलीकॉम 11 बैंकों के कंसोर्टियम से जुड़ी थी, जिसने कंपनी को कुल 735 करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया था। आरोप है कि कंपनी और उसके अधिकारियों ने आपराधिक साजिश के तहत इस ऋण राशि का दुरुपयोग किया और बैंक के साथ धोखाधड़ी की।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

CBI ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया है। इसमें लोक सेवकों पर पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार के आरोप शामिल हैं। यह कार्रवाई अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों पर चल रही जांच का हिस्सा मानी जा रही है।

पैकेज केंद्र से मंजूर राशि से 35.56 करोड़ अधिक का मिला फंड

केंद्र ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए खोला खजाना

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र ने छह प्रमुख योजनाओं के लिए कुल 723.62 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था। हालांकि, राज्य के कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को देखते हुए, केंद्र ने वास्तविक रूप में 759.18 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। यह मंजूर राशि से 35.56 करोड़ रुपये अधिक का अतिरिक्त फंड है।कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 'कृषि यंत्रीकरण' और 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) योजनाओं को किसानों का भारी समर्थन मिला है। कृषि यंत्रीकरण के लिए जहां 99.19 करोड़ रुपये मंजूर थे, वहीं केंद्र ने 123 करोड़ रुपये दिए। इसी तरह, 'प्रति बूंद अधिक उत्पादन' योजना के लिए 286 करोड़ रुपये के मुकाबले 357.95 करोड़ रुपये का वास्तविक फंड प्राप्त हुआ है।

1800 करोड़ के अनुदान का वितरण

दिसंबर तक चली इस प्रक्रिया में 2012 से लंबित पड़े कई आवेदनों का निपटारा किया गया। लगभग 10 लाख लाभार्थियों ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की। विभाग के अनुसार, कृषि यंत्रीकरण और सूक्ष्म सिंचाई को मिलाकर कुल 3,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनी थी। इसमें से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अब तक 1,800 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित कर दिया है।

लॉटरी सिस्टम बंद होने से किसानों को फायदा

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होती है। पहले इन योजनाओं के लाभार्थियों को चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जिसमें अक्सर जरूरतमंद किसान पीछे रह जाते थे। मौजूदा नीतियों के तहत लॉटरी सिस्टम को बंद कर 'पहले आओ, पहले पाओ' का सिद्धांत अपनाया गया। इस पारदर्शी प्रक्रिया के कारण ही केंद्र से मिलने वाले अनुदान का वितरण तेजी से संभव हो पाया है।

दीवाली के समय कृषि समृद्धि योजना के तहत लगभग 48 लाख आवेदनों को पूर्व-सहमति (Pre-sanction) दी गई थी।

शिक्षा के मंदिर पर दाग

महिला टीचर को अश्लील मैसेज भेजने वाला ट्रस्टी का बेटा हिरासत में

सगांव के स्कूल में मनसे कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा, मानपाड़ा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

डीबीडी संवाददाता | डोंबिवली

डोंबिवली के सगांव इलाके में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम स्कूल की गरिमा उस वक्त तार-तार हो गई, जब स्कूल ट्रस्टी के बेटे पर एक महिला शिक्षिका को अश्लील संदेश भेजने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। 26 मार्च 2026 को हुए इस हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

स्कूल परिसर में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा

मनसे कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुँचने से वहां करीब एक घंटे तक तनाव बना रहा। कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ती देख मानपाड़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और मामला शांत कराया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया।

पिता ने बेटे का बचाव नहीं किया

हैरानी की बात यह है कि आरोपी के पिता, जो खुद एक रिटायर्ड प्रोफेसर और स्कूल ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपने बेटे का बचाव नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि उनका बेटा दोषी पाया जाता है, तो कानून के तहत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस की जांच और FIR

मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस अब शिक्षिका के बयान दर्ज कर रही है और आरोपी के फोन से भेजे गए डिजिटल सबूतों (मैसेज और वीडियो) की फोरेंसिक जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

सगांव (डोंबिवली) स्थित एक नामी अंग्रेजी स्कूल के ट्रस्ट में शामिल एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर का 31 वर्षीय बेटा, महिला शिक्षिका को लंबे समय से परेशान कर रहा था। आरोप है कि उसने शिक्षिका को अश्लील मैसेज, भद्दे वीडियो क्लिप भेजे और यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। पीड़ित शिक्षिका ने शुरुआत में आरोपी को नजरअंदाज किया और उसका नंबर ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुईं। परेशान होकर शिक्षिका ने स्थानीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्कूल पहुँचे और विरोध प्रदर्शन किया।

सोलापुर मंडल में विश्व क्षय रोग दिवस पर जागरूकता अभियान

डीबीडी संवाददाता | सोलापुर

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने 24 मार्च 2026 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर टीबी-मुक्त भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह कार्यक्रम डॉ. कोटनीस मेमोरियल मंडल रेल अस्पताल, सोलापुर और पॉलीक्लिनिक, वाडी में आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रेल लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्षय रोग (टीबी) के बारे में जागरूक करना था। इसमें टीबी की रोकथाम, समय पर जांच और प्रभावी उपचार के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।

विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

देगांव पीएचसी की चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनाली महिंद्राकर ने अपने व्याख्यान में टीबी के कारण, लक्षण और फैलने के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समय पर पहचान और उपचार के निर्धारित नियमों का पालन करने पर जोर दिया।

स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका पर जोर

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) सोलापुर, डॉ. मंजूनाथ जी. एस. ने टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और समाज की भागीदारी इस अभियान में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ आदतें अपनाने और टीबी से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने की अपील की। पॉलीक्लिनिक, वाडी में मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुनंदन और डॉ. श्रवण द्वारा भी इसी तरह का जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिससे अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित हुई। इन कार्यक्रमों में करीब 130 लाभार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जो जागरूकता के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

पीड़ितों को 24 घंटे में मदद का अल्टीमेटम

प्रशासन की लापरवाही पर भड़के मंत्री प्रताप सरनाईक

डीबीडी संवाददाता | मीरा रोड

मीरा रोड के प्लेजेंट पार्क स्थित कृष्णस्थल कॉम्प्लेक्स के गोदाम में लगी भीषण आग ने न केवल इमारतों को, बल्कि कई आम लोगों के सपनों को भी खाक कर दिया है। इस हृदयविदारक घटना का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिले के पालक मंत्री माननीय श्री प्रताप सरनाईक ने आज घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने न केवल स्थिति का जायजा लिया, बल्कि प्रशासनिक सुस्ती पर कड़ा प्रहार करते हुए दोषी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

> "मीरा रोड की इस आग में सिर्फ घर नहीं जले, बल्कि मेरी माताओं-बहनों की मेहनत और आम आदमी के सपने खाक हुए हैं। इस हादसे के लिए नगर निगम की सुस्ती और भ्रष्ट कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। मैंने प्रशासन को साफ कर दिया है कि 24 घंटे में पंचनामा पूरा करें, वरना कुर्सियां तोड़ने वाले अधिकारियों को उनकी जगह दिखा दी जाएगी। मैं यहाँ मंत्री के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में आया हूँ। जब तक आखिरी पीड़ित को उसका हक और घर नहीं मिल जाता, मैं शांत नहीं बैठूँगा।
>
> – प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

घर-घर जाकर बंधाया ढाँढस; तत्काल मदद के आदेश

मंगलवार, 24 मार्च की रात लगी इस भीषण आग ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि पास की चार इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। कई मध्यमवर्गीय परिवारों का संसार इस आग में जलकर भस्म हो गया। इस विभीषिका को देख द्रवित हुए मंत्री सरनाईक ने प्रत्येक प्रभावित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। नागरिकों का आक्रोश सुनने के बाद उन्होंने घटनास्थल से ही मीरा-भायंदर नगर निगम आयुक्त, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और तहसीलदार को फोन कर सख्त लहजे में निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगले 24 घंटों के भीतर हर प्रभावित घर का पंचनामा पूरा हो जाना चाहिए। यदि पीड़ित नागरिकों को आर्थिक सहायता से वंचित रखा गया, तो अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

अवैध निर्माणों पर अब चलेगा बुलडोजर

मंत्री सरनाईक ने इस संकट के लिए नगर निगम के भ्रष्टाचार और अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को अवैध रूप से चल रहे गोदामों, शेड और स्टूडियो पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नगर निगम ने समय रहते इन अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाया होता, तो आज यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती।

अग्निशमन दल की देरी पर बरसे मंत्री

स्थानीय निवासियों के अनुसार, आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों को पहुँचने में करीब 40 से 50 मिनट की देरी हुई। इसी देरी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। इस पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मंत्री सरनाईक ने इस गंभीर लापरवाही की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं।

मराठी मानुस के साथ सरकार मजबूती से खड़ी

इस क्षेत्र में मराठी भाषियों की संख्या अधिक है। नागरिकों को आश्वासन देते हुए प्रताप सरनाईक ने कहा, किसी भी स्थिति में मराठी व्यक्ति पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रत्येक पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाना नगर निगम की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के पीछे ढाल बनकर खड़ी है।

जेएमए की नई महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी का गठन, संजय निराले बने अध्यक्ष

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन (जेएमए) ने महाराष्ट्र राज्य के लिए अपनी नई वर्किंग कमेटी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 मार्च को निष्पक्ष रूप से संपन्न हुए चुनावों में वरिष्ठ पत्रकार संजय निराले को प्रदेश अध्यक्ष और विनायक गुलगुले को कार्याध्यक्ष चुना गया है। कमेटी में संजय पवार महासचिव, राजीव मोहन मिश्रा व सुचिता बिराजदार राज्य सलाहकार और दत्तात्रय सुर्यवंशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को स्टेट इंचार्ज सुधीर शर्मा के मार्गदर्शन में पॉलिसी एक्सपर्ट संजीव विश्वकर्मा और राजीव मोहन मिश्रा ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिसमें उपाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए भी अन्य सक्रिय सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

पत्रकार सुरक्षा और कल्याण के लिए जेएमए की प्रतिबद्धता

नवनियुक्त अध्यक्ष संजय निराले और प्रदेश प्रभारी सुधीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य असंगठित पत्रकारों को एकजुट कर उनके हितों की रक्षा करना है। नवनिर्वाचित टीम ने पत्रकारों की सुरक्षा, आर्थिक कल्याण, पेंशन नीति और डिजिटल मीडिया कर्मियों को मान्यता दिलाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करने का संकल्प लिया है। सुधीर शर्मा ने चिंता व्यक्त की कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हो रहा है और कई श्रमजीवी पत्रकार आज भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। जेएमए इन चुनौतियों के समाधान के लिए एक ठोस कार्ययोजना के तहत पत्रकारों के मान-सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर महाजाम

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/पुणे

मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब लोनावला के पास घाट सेक्शन में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। हजारों वाहन कई किलोमीटर तक फंसे रहे और लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। घाट खंड में हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें ही नजर आ रही थीं। कई जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया, जिससे यात्रियों को गाड़ियों में ही कैद रहना पड़ा।

लॉन्ग वीकेंड बना जाम की बड़ी वजह

26 से 29 मार्च तक चार दिनों के लंबे वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में मुंबई से लोग लोनावला, खंडाला और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों के लिए निकले थे। अचानक बढ़े वाहनों के दबाव ने एक्सप्रेसवे पर स्थिति बिगाड़ दी। ट्रैफिक विभाग के अनुसार, मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य और वाहनों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी इस जाम का मुख्य कारण रही। अधिकारियों ने पहले ही देरी की चेतावनी दी थी, लेकिन सुबह के पीक ऑवर में स्थिति और गंभीर हो गई। जाम से परेशान यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, "मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को 'स्लो-वे' घोषित कर देना चाहिए। 320 रुपये टोल देने के बाद भी हर दिन 45 मिनट की देरी मिल रही है।" यात्रियों ने सरकार से 'मिसिंग लिंक' परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि घाट सेक्शन के घुमावदार रास्तों को बाईपास करने वाली यह परियोजना ही स्थायी समाधान दे सकती है। स्थिति को संभालने के लिए लोनावला के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि धीरे-धीरे ट्रैफिक सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यात्रियों को अभी भी देरी का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे में 11,127 एएलपी पदों पर भर्ती,15 मई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय रेल ने सहायक लोको पायलट (ALP) के 11,127 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से 14 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। सोलापुर मंडल द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे त्वरित जांच और सत्यापन के लिए अपने आधार कार्ड का विवरण (नाम और जन्मतिथि) 10वीं के प्रमाणपत्र के अनुसार अपडेट रखें। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक पोर्टल्स पर ही भरोसा करने और बिचौलियों या ठगों से सावधान रहने की सख्त हिदायत दी गई है। रेल मंत्रालय ने भर्ती प्रणाली में सुधार करते हुए 'वार्षिक भर्ती कैलेंडर' लागू किया है, जिससे अब अभ्यर्थियों को हर साल रोजगार के निश्चित अवसर प्राप्त होंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रुप 'सी' पदों की भर्ती, प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करना है ताकि भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

अंबरनाथ पंचायत समिति में विकास कार्यों की समीक्षा

डीबीडी संवाददाता | अंबरनाथ

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव ने अंबरनाथ के रहाटोली ग्राम पंचायत का दौरा कर मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का विस्तृत आकलन किया गया। इस मौके पर गट विकास अधिकारी अजीत देसाई, ग्राम पंचायत सरपंच एवं प्रशासक राजश्री रूपेश रेवाले, ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश गणपत वारघड़े, जिला परिषद स्कूल के प्राचार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण

दौरे के दौरान गांव में बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था, पानी आपूर्ति योजना, घरकुल (आवास) योजना, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर संतोष व्यक्त किया।

महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर विशेष फोकस

महिला सशक्तिकरण के लिए लागू योजनाओं की भी समीक्षा की गई। स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के कार्यों और उनकी भागीदारी को सराहा गया, साथ ही इन योजनाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। रंजीत यादव ने ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता, जनभागीदारी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की गई। साथ ही भविष्य में भी इसी तरह के गुणवत्तापूर्ण कार्य जारी रखने की अपील की गई।

अश्विनी बिद्रे मर्डर केस

कुरुंदकर की जमानत पर नवी मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

अश्विनी बिद्रे हत्याकांड के मुख्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर की जमानत प्रक्रिया को लेकर नवी मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बिद्रे परिवार और सरकारी वकील ने दावा किया है कि आरोपी को राहत दिलाने के लिए पुलिस स्तर पर सक्रियता दिखाई जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया पत्र

घरात द्वारा भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह-पुलिस आयुक्त संजय येनपुरे और अपराध शाखा के उपायुक्त अमित काळे को भी भेजी गई है।

पनवेल कोर्ट से उम्रकैद, अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका

पनवेल सत्र न्यायालय ने 21 अप्रैल 2025 को अभय कुरुंदकर को इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है।

परिवार को वेबसाइट से मिली सुनवाई की जानकारी

अश्विनी बिद्रे के पति राजू गोरे ने बताया कि उन्हें आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने अदालत की वेबसाइट से जानकारी हासिल की, जिसमें मार्च 2026 में सुनवाई की तारीख तय होने का पता चला।

पुलिस पर प्रभाव डाल रहा आरोपी

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी की ओर से पुलिस पर प्रभाव डाला जा रहा है। सरकारी वकील ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात सामने आता है, तो इसकी जानकारी उच्च न्यायालय को दी जाएगी।

सरकारी वकील को अंधेरे में रखने का आरोप

सरकारी वकील प्रदीप घरत ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना जानकारी दिए जमानत से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में उन्होंने नवी मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है।

सुनवाई के दौरान पुलिस की अनुपस्थिति पर सवाल

18 मार्च 2026 को हुई सुनवाई में संबंधित पुलिस अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं थे और न ही पुलिस की ओर से कोई प्रतिनिधि सरकारी वकील से संपर्क करने पहुंचा। इससे मामले में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका के आरोप और गहरा गए हैं।

बाइक सवार बदमाशों ने 1.10 लाख की चेन छीनी

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

शहर के ढोकली परिसर में देर रात चेन स्नैचिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बाइक पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति के गले से करीब 1.10 लाख रुपये की सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए।

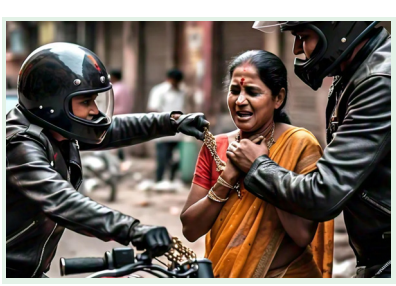

कार पार्क करते ही बनाया निशाना

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता अभिषेक खंडेलवाल (33), कोलशेत रोड निवासी, 22 मार्च की रात करीब 9:30 बजे हाइलैंड इलाके से घर लौट रहे थे। ढोकली स्थित शरद चंद्र पवार स्टेडियम के सामने उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे पार्क की और पास की दुकान पर चले गए। लौटकर जैसे ही वे कार में बैठने लगे, तभी बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया।

गर्दन पकड़कर छीनी चेन

शिकायत के मुताबिक, ढोकली चेकपॉइंट की ओर से बाइक पर आए दो युवकों में से एक ने अभिषेक की गर्दन पकड़ ली और जबरन उनके गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी तुरंत फरार हो गए। चोरी गई चेन की कीमत करीब 1 लाख 10 हजार रुपये बताई जा रही है।

कापूरबावड़ी पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के बाद कापूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में जबरन चोरी का मामला दर्ज किया गया है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मंजुषा भोंगले के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।

मेलघाट में जलस्रोत योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

मंत्री गुलाबराव पाटील ने की समीक्षा बैठक

डीबीडी संवाददाता | अमरावती/मुंबई

मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से राज्य के जलापूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटील की अध्यक्षता में मंत्रालय, मुंबई में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेलघाट के विधायक केवलराम काले ने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

जल स्रेत और प्रगति पर हुआ मंथन

समीक्षा के दौरान जल स्रोतों की उपलब्धता, योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति, सामने आ रही चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो। विधायक केवलराम काले ने मेलघाट के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त जल संकट को गंभीर बताते हुए लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने जल समस्या के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया। जलापूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटील ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा किया जाए और नागरिकों को नियमित व स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

7 जलापूर्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

बैठक में मेलघाट क्षेत्र के बागलिंगा, गौलखेडा बाजार, चुरणी, शहापुर, हिराबंबई, गडगा और रानापीसा सहित आसपास के गांवों में चल रही सात क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

मुंबई में रफ्तार का कहर

पत्नी और 3 महीने के बेटे से मिलने जा रहे युवक की 'हिट एंड रन' में मौत

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई की भागती-दौड़ती जिंदगी ने एक और हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। अंधेरी पूर्व से माटुंगा अपनी पत्नी और महज 3 महीने के मासूम बेटे से मिलने निकले 24 वर्षीय नीलकंठ विजय इंगोले अब कभी घर नहीं लौटेंगे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुए एक भीषण 'हिट एंड रन' हादसे में नीलकंठ की मौके पर ही मौत हो गई। विले पार्ले पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

अंधेरी (पूर्व) की टोपलीवाड़ी चॉल

में रहने वाले नीलकंठ इंगोले अपने परिवार के मुख्य आधार थे। करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने आर्या नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था और तीन महीने पहले ही उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। आर्या फिलहाल माटुंगा स्थित अपने मायके में रह रही थी, इसलिए नीलकंठ अक्सर उनसे मिलने वहां जाया करते थे। 24 मार्च की रात करीब 11:30 बजे नीलकंठ अपनी बाइक से माटुंगा के लिए निकले थे। हादसा रात करीब 12:15 बजे विले पार्ले पूर्व स्थित सेंटॉर ब्रिज के ढलान पर हुआ। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने नीलकंठ की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नीलकंठ सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात यह रही कि घायल युवक की मदद करने के बजाय, अज्ञात चालक उन्हें लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण नीलकंठ ने दम तोड़ दिया।

मासूम के सिर से उठा पिता का साया

इस हृदयविदारक घटना से इंगोले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महज तीन महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाने से पूरे इलाके में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि जो शख्स कुछ देर पहले उनसे मिलकर निकला था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। विले पार्ले पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत का कारण बनने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाईवे पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि अपराधी वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दाभोलकर-फडणवीस तुलना पर सियासी संग्राम

सपकाल ने सुले से बयान वापस लेने को कहा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में डॉ. नरेंद्र दाभोलकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना को लेकर विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के बयान को भ्रामक और आक्रोश पैदा करने वाला बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की है।

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर और देवेंद्र फडणवीस की तुलना किसी भी स्तर

पर संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों की विचारधारा, कार्यशैली और विरासत पूरी तरह भिन्न है, इसलिए इस तरह की तुलना करना गलत संदेश देता है। सपकाल ने कहा कि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ने अंधविश्वास उन्मूलन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने शिव, शाहू, फुले और आंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और उनका योगदान समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी विचारधारा प्रगतिशील सोच को पीछे धकेलने वाली है और समाज को अंधविश्वास की ओर ले जाने वाली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फडणवीस का रुख प्रतिगामी विचारों को बढ़ावा देने वाला है।

संजय राऊत के कांग्रेस में शामिल होने के दावे पर सियासत तेज

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

भाजपा ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राऊत को लेकर बड़ा दावा करते हुए राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवनाथ बन ने आरोप लगाया कि राऊत जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और राज्यसभा सदस्यता बनाए रखने की कोशिश में हैं।

नवनाथ बन ने कहा कि संजय राऊत का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा है कि राऊत को यह एहसास हो गया है कि उद्धव ठाकरे उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेंगे, इसलिए वे नया राजनीतिक रास्ता तलाश रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राऊत लंबे समय से पर्दे के पीछे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है और स्थिति 'ठाकरे बनाम राऊत' जैसी बनती दिख रही है।

हिंदुत्व के मुद्दे पर भी घेरा

नवनाथ बन ने राऊत की हिंदुत्व पर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग बालासाहेब ठाकरे के विचारों से हटकर कांग्रेस के साथ जाने की सोचते हैं, उन्हें भाजपा पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा ने राऊत पर यह भी आरोप लगाया कि वे ठाकरे गुट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के इन दावों और आरोपों पर अभी तक संजय राऊत या शिवसेना (यूबीटी) की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें राऊत के जवाब और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हैं।

एमएमआरडीए को मिली 84,000 एकड़ जमीन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक भूमि हस्तांतरण मंजूर कर दिया है। 26 मार्च 2026 को जारी सरकारी संकल्प के अनुसार, MMRDA को लगभग 84,000 एकड़ सरकारी जमीन सौंपी जा रही है। यह कदम न केवल बुनियादी ढांचे को रफ्तार देगा, बल्कि मुंबई को 'ग्लोबल हब' बनाने के 'मुंबई 3.0' विजन को भी हकीकत में बदलेगा। यह विशाल भूमि बैंक केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। इसमें ठाणे, अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण, अलीबाग, पनवेल, पालघर और वसई जैसे उभरते हुए

लॉजिस्टिक्स पार्क और नए 'ग्रोथ सेंटर' का रास्ता साफ

शहरों के 1,324 गांव शामिल हैं। इन इलाकों में अब वर्ल्ड-क्लास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बिजनेस हब और बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की कमी नहीं होगी।

कर्ज के बजाय अपनी कमाई से विकास

वर्तमान में MMRDA 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स (जैसे 300 किमी का मेट्रो जाल) पर काम कर रही है। अब तक इसके लिए विदेशी बैंकों से कर्ज लेना पड़ता था। अब इस आवंटित जमीन को बेचकर या लीज पर देकर (Monetization) प्राधिकरण खुद पैसा जुटा सकेगा। इसे FY27 के लिए 'वित्तीय क्लोजर' कहा जा रहा है।

नीति आयोग और मुंबई 3.0 का सपना

सरकार इसे 'मुंबई 3.0' कह रही है। इसका मकसद मुंबई को केवल एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक इंजन बनाना है। इसमें ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पर ज़ोर है, यानी मेट्रो स्टेशनों के आसपास ही ऑफिस, घर और बाज़ार बसाना ताकि लोगों को लंबी यात्रा न करनी पड़े।

सरकार की कड़ी शर्तें और 25% की हिस्सेदारी

जमीन मुफ्त नहीं मिल रही है, सरकार ने कुछ पेंच भी कसे हैं:

कमाई का हिस्सा: इस जमीन के विकास से होने वाली कुल आय का 25% हिस्सा MMRDA को राज्य सरकार को देना होगा।

डिजिटल रिकॉर्ड: हर इंच जमीन का हिसाब ऑनलाइन रखना होगा।

स्थानीय अनुमति: ग्राम पंचायतों या जिला परिषदों की जमीन छूने से पहले उनकी लिखित मंजूरी अनिवार्य है।

सड़क हादसों में मौतें घटाने के लिए सरकार सख्त

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में PM-RAHAT योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक में मंत्री आबिटकर ने कहा कि दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा, जिसे 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है, घायल की जान बचाने के लिए

पीएम-RAHAT योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

सबसे अहम होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक कारणों से किसी भी मरीज के इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए।

1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

PM-RAHAT योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि जरूरत के समय लोग इसका लाभ उठा सकें। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में तुरंत '112' (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम) पर कॉल करें, ताकि समय पर सहायता मिल सके और ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें।

विक्रोली में 2.03 करोड़ रुपए की चरस जब्त, दो गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

क्राइम ब्रांच (यूनिट 7) ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सफलता हासिल की है। विक्रोली के पार्कसाइट इलाके में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने दो तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा है। उनके पास से कुल 2 किलो 30 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.03 करोड़ रुपए आंकी गई है।

क्राइम ब्रांच यूनिट 7 को 25 मार्च को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुंबई में चरस की एक बड़ी खेप पहुंचने वाली है।

जानकारी के अनुसार, विक्रोली पश्चिम में एक किराए के कमरे का इस्तेमाल ड्रग्स छिपाने और बेचने के लिए किया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आत्माजी सावंत के मार्गदर्शन में टीम ने तुरंत जाल बिछाया। जैसे ही दो संदिग्ध प्लास्टिक बैग लेकर कमरे से बाहर निकलने लगे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा।

पुलिस ने इस मामले में किशोर शेडगे

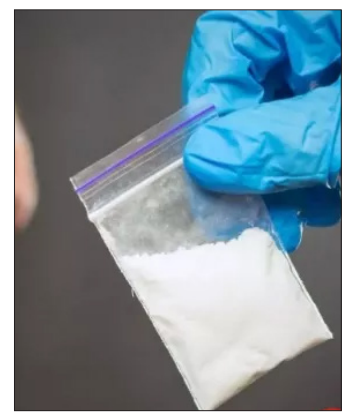

और राजेश गावडे नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ड्रग्स स्टोर करने के लिए महज 5 दिन पहले ही वह कमरा किराए पर लिया था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए उन्होंने घर का कोई लिखित एग्रीमेंट (Agreement) नहीं किया था, ताकि पकड़े जाने पर उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या पता न मिल सके।

ड्रग्स रैकेट के मुख्य किरदारों का खुलासा

प्रारंभिक जांच के दौरान आरोपी किशोर शेडगे ने कबूल किया कि जब्त किया गया चरस उसे प्रणय मोरे ने ओम कामटे के जरिए मुहैया कराया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अब इन दोनों फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं, जिनसे उनके नेटवर्क और संपर्कों की गहनता से जांच की जा रही है।

बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह की आशंका

मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस बात की जांच कर रही है कि यह रैकेट कितना बड़ा है और इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं। पुलिस की विभिन्न टीमें फरार आरोपियों और मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस को संदेह है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिससे शहर में चल रहे नशे के अवैध व्यापार की कमर टूटेगी।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने पात्र फेरीवालों पर न हो ज्यादती: निरुपम

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरुपम ने मुंबई में अधिकृत फेरीवालों के प्रति हो रही प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने की आड़ में उन मेहनतकश फेरीवालों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, जो कानूनी रूप से पंजीकृत हैं और अपना घर चला रहे हैं। संजय निरुपम ने मुंबई मनपा और पुलिस

प्रशासन से अनुरोध किया है कि 'बांग्लादेशी घुसपैठियों' के नाम पर अधिकृत हॉकरों को परेशान करना बंद किया जाए। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पुलिस को चुनौती दी कि वे पिछले दो महीनों में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी फेरीवालों के सटीक आंकड़े और सबूत सार्वजनिक करें। निरुपम के अनुसार, मुंबई में लगभग 1 लाख से अधिक पंजीकृत फेरीवाले हैं, जिन्हें एक तरफ केंद्र सरकार लोन और आर्थिक मदद दे रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने इस 'दोहरी भूमिका' को गलत बताते हुए कहा कि केवल स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट करना अन्यायपूर्ण है।

जांच के दायरे को बढ़ाने और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का संकल्प

निरुपम ने सुझाव दिया कि यदि प्रशासन वास्तव में अवैध नागरिकों की पहचान करना चाहता है, तो उसे केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मांग की कि लेदर, टेक्सटाइल फैक्ट्रियों, जरी उद्योग और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों की भी गहन जांच होनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) को पत्र लिखेंगे।

महाराष्ट्र में बेमौसम आफत की आहट

30-31 मार्च को आंधी-तूफान और ओले गिरने की चेतावनी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में खेती-किसानी और आम जनजीवन के लिए अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। राज्य के बड़े हिस्से में 30 और 31 मार्च के दौरान आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, बारिश और तूफान का मुख्य केंद्र मराठवाड़ा, पश्चिमी विदर्भ, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से रहेंगे। विशेष रूप से कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा से सटे दक्षिणी जिलों में 'लोकल थंडरस्टॉर्म' (स्थानीय स्तर पर गरज-चमक) की स्थिति बन सकती है।

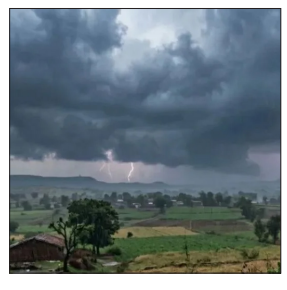

किसानों के लिए सलाह

चूंकि अभी रबी की फसलों (जैसे गेहूं, चना, ज्वार) की कटाई का पीक सीजन चल रहा है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि कटी हुई फसल को तुरंत खलिहान से सुरक्षित गोदामों में पहुँचाएं। यदि फसल खेत में ही है, तो उसे तिरपाल या प्लास्टिक से ढकने का पुख्ता इंतजाम करें।

दोपहर के बाद करवट लेगा मौसम

अनुमान है कि 30 मार्च को दोपहर के बाद अचानक बादल छाएंगे और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। यह स्थिति 31 मार्च को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बनी रहेगी। कुछ जगहों पर ओले (Ice pellets) गिरने की भी संभावना है, जो खड़ी और कटी फसलों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।

मध्य रेल
संशोधन कार्य

खुली निविदा सूचना संख्याः सीआरएमयूएम एमईसीएचएनसीसीओ 1642025 दिनांकः 18.03.2026 कार्य का नामः मुंबई डिवीजन के वाडीबंदर और माज़गाँव कोचिंग डिपो के सभी एलएचबी प्रकार के कोचों में ईपीपीएफएस की जल दाब नियंत्रक इकाई को नीचे से हटाकर शौचालय की संलग्न दीवार के पीछे, कोच के अंदर स्थानांतरित करने का संशोधन कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः** ₹63,82,089/- रुपये तिरसठ लाख बयासी हजार नवासी केवल) **बयाना राशिः** ₹1,27,600/- (रुपये एक लाख सत्ताईस हजार छह सौ केवल) **निविदा दस्तावेज शुल्कः** निशुल्क. **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समयः** 08.04.2026 को 15:00 बजे तक निविदाएं केवल वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से ई-टेंडरिंग प्रारूप में स्वीकार की जाएंगी। निविदा दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे। 1028

मध्य रेल
स्क्रीनिंग कार्य।

खुली ई-निविदा संख्याः BD.WRB.41.Paint Shop. तिथिः 18.03.2026 कार्य का विवरणः एक वर्ष की अवधि के लिए 1200 वैगनों के लिए वैगन मरम्मत कार्यशाला, बडनेरा में बॉक्सएन बॉक्सएनएचएल, बीसीएन, बीआरएन, बीएलसी, वैगनों (सभी वेरिएंट) की पेंटिंग और स्टेंसिलिंग (स्क्रीनिंग) कार्य। **अनुमानित लागतः** ₹2,27,76,894.54/-, **नविदा प्रपत्रका शुल्क :** कुछ नहीं. **ईएमडीः** ₹2,63,900/-. **समापन अवधिः** 12 महीने. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं अवधि दि. **22.04.2026 को 15.00 बजे है।** ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की आधिकारिक वेबसाइटः **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे। 1027

मध्य रेल
भुसावल मंडल
यार्ड री-मॉडलिंग कार्य

टेंडर नोटिस नं. भुसावल_ इलेक्ट्रिक_टीआरडी_18_2026 दिनांक 24.03.2026. **कार्य का नाम** मध्य रेल के भुसावल मंडल में वलगांव एवं चांदुर बाजार स्टेशनों पर यार्ड री-मॉडलिंग कार्य के अंतर्गत 25 केवी, एकल फेज, एसी ओएचई कार्यों का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग किया जाना है। **कार्य की लागतः** ₹1,35,81,568.10 **बयाना राशिः** ₹2,71,600.00 **निविदा जमा करने की अंतिम तारीख, समय** 17.04.2026 को 15.00 बजे तक **अतिरिक्त जानकारी के लिए वेब साइट का पता** **www.ireps.gov.in**

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे। 28

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
एलसी गेट पर पेडस्टल आदि का प्रतिस्थापन

निविदा सूचना संख्याः सोला-एन-टी-2025-26-48 दिनांक 24.03.2026 भारत के राष्ट्रपति की ओर से डीआरएम (एस एंड टी) कार्यालय, मध्य रेलवे, सोलापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। **इलाके के साथ काम का नामः** सेंट्रल रेलवे के सोलापुर मंडल में एलसी गेटों पर पुराने हो चुके गेट पेडस्टल और संबंधित सहायक उपकरणों का प्रतिस्थापन करना। **निविदा संख्याः** सोला एन-टी-2025-26-48 **कार्य अनुमानित की लागतः** ₹1,59,35,211.54 **टेंडर फॉर्म कीमतः** NIL **जमा की जाने वाली धरोहर राशिः** ₹2,29,700 **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 12 महीने **निविदा के समापन की तिथि समयः 20.04.2026 15:30** बजे विवरण **ireps** वेबसाइट में उपलब्ध हैं। शुद्धिपत्र संशोधन यदि कोई हो तो केवल उपरोक्त ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। केवल ऑनलाइन निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। मैनुअल/डाक/ई-मेल, फैक्स, हस्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के साथ तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करें और इसे **www.ireps.gov.in** पर पंजीकृत करें। बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से या बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और मूल बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (अर्थात बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर) जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** देखें।

असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है 07

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
सिग्नलिंग कार्य

निविदा सूचना संख्याः सोला-एन-टी-2025-26-47 दिनांक 24.03.2026. भारत के राष्ट्रपति की ओर से डीआरएम (एस एंड टी) कार्यालय, मध्य रेलवे, सोलापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए सशम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर औनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। **इलाके के साथ काम का नामः** सोलापुर मंडल के सोलापुर-कुर्दुवाड़ी खंड में LC-40 और LC-42 के स्थान पर आरओबी के निर्माण से संबंधित सिग्नलिंग कार्य करना। **निविदा संख्याः** सोला-एन-टी 2025-26-47, **कार्य की अनुमानित लागतः** ₹1,33,43,324.27, **टेंडर फॉर्म की कीमतः** NIL, **जमा की जाने वाली धरोहर राशिः** ₹2,16,700 **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 12 महीने, **निविदा के समापन की तिथि और समयः** 20/04/2026 15:30 बजे विवरण ireps वेबसाइट में उपलब्ध हैं। शुद्धिपत्र/ संशोधन यदि कोई हो तो केवल उपरोक्त ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। केवल ऑनलाइन निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। मैनुअल/डाक/ई-मेल, फैक्स, हस्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के साथ तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करें और इसे **www.ireps.gov.in** पर पंजीकृत करें। बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से या बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और मूल बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (अर्थात बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर) जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** देखें।

असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है 06

मध्य रेल
अधिसूचना

निम्नलिखित पदों के लिए भर्ती हेतु 06/04/2026 और 07/04/2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।

पद का नाम	पद की योग्यताएं	साक्षात्कार की तिथि	पदों की संख्या
डेंटल	BDS/MDS वांछनीय (न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव)	06/04/2026	1
जीडीएमओ	एमबीबीएस	07/04/2026	1
रेडियोलॉजिस्ट	एमडी/डीएनबी डिग्री/डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तीन वर्षों का क्लिनिकल अनुभव अनिवार्य।	07/04/2026	1

कुल 3 पद ओपन मार्केट और सेवानिवृत्त रेलवे, राज्य और केंद्रीय सरकार के डॉक्टरों के लिए, पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर: (A) ओपन मार्केट: अनुबंध की तिथि से एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए, जिसे प्रति वर्ष आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है, जो 12 अवधियों से अधिक न हो या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या जब तक UPSC द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध न हो, जो भी पहले हो। (B) सेवानिवृत्त डॉक्टर, रेलवे, राज्य और केंद्रीय सरकार के: अनुबंध की तिथि से एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए, जिसे प्रति वर्ष आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है, जो 7 अवधियों से अधिक न हो और 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या जब तक UPSC द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध न हो, जो भी पहले हो। यहां उल्लिखित पदों को, प्रशासन की विवेकाधिकार पर, विशेषज्ञों की अनुपलब्धता की स्थिति में GDMOs (जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स) से भरा जा सकता है। विस्तृत अधिसूचना के लिए कृपया वेबसाइट **www.cr.indianrailways.gov.in** पर जाएं। **www.cr.indianrailways.gov.in**> About Us > Head Quarter > Personnel > Recruitment > Contract Medical Practitioners - 01 of 2025

असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है 1024

संपादकीय

दहेज लोभियों के लिए अब कोई 'सुरक्षित गलियारा' नहीं

देश की सर्वोच्च अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी की जमानत रद्द करते हुए जो कड़ी टिप्पणी की है, वह केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि समाज के गिरते नैतिक मूल्यों पर तीखा प्रहार है। अदालत ने साफ कहा कि जहां मानवीय संवेदनाएं कुचल दी गई हों, वहां कानून की तकनीकी दलीलों के आधार पर रियायत की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यह संदेश उन लोगों के लिए सीधा चेतावनी है, जो दहेज को अधिकार या परंपरा के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश करते हैं।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद", लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि विवाहिता को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, तो आरोपी को खुला छोड़ना न्याय के साथ समझौता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत केवल आरोपी का अधिकार नहीं, बल्कि पीड़ित के न्याय और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन का विषय है।

दहेज प्रथा आज भी एक गहरी सामाजिक बीमारी बनी हुई है। आधुनिक शिक्षा और विकास के दावों के बावजूद, यह कुप्रथा खत्म नहीं हो रही। विवाह, जो दो आत्माओं का पवित्र बंधन होना चाहिए, उसे कई परिवार आज भी लाभ के सौदे में बदल देते हैं। अदालत की टिप्पणी इस मानसिकता पर सीधा प्रहार है। यह हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारी सामाजिक सोच अभी भी पिछड़ी हुई है।

फैसले का एक अहम पहलू जांच एजेंसियों और निचली अदालतों की जवाबदेही भी है। कई मामलों में कमजोर जांच या साक्ष्यों की अनदेखी के कारण आरोपी बच निकलते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय तभी संभव है जब जांच निष्पक्ष और साक्ष्य मजबूत हों। केवल सख्त कानून बना देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।

न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न को 'निरंतर अपराध' मानते हुए यह भी कहा कि यदि वर्षों बाद भी प्रताड़ना जारी है, तो उसे पुराना मामला कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निचली अदालतों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय विशेष सतर्कता बरतें और पीड़ित की पीड़ा को समझें।

अंततः, यह फैसला न्यायपालिका की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां पीड़ित की आवाज को अनसुना नहीं किया जाएगा। यह केवल सजा देने का सवाल नहीं, बल्कि समाज में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास है जहां कोई भी बेटी दहेज की भेंट न चढ़े। अब समय आ गया है कि समाज भी कानून के साथ खड़ा होकर इस कुप्रथा का पूरी तरह बहिष्कार करे।

दहकते पश्चिम एशिया में वैश्विक संकट का आगाज

देवेंद्रनाथ जैसवार

> इस युद्ध का सबसे भयावह असर दुनिया की जेब पर पड़ रहा है। ईरान द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को आंशिक रूप से बंद करने और गैर-मैत्रीपूर्ण जहाजों पर शुल्क लगाने के फैसले ने वैश्विक व्यापार को पंगु बना दिया है। 'द गार्डियन' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में गैस की कीमतों में 30% और डीजल में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यह केवल ऊर्जा का संकट नहीं है, बल्कि खाद और परिवहन महंगा होने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है।

28 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ ईरान-अमेरिका युद्ध अब अपने पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। जिसे अमेरिका ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और इजरायल ने 'रोअरिंग लायन' का नाम दिया, वह अब केवल दो देशों के बीच की सैन्य झड़प नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी संकट बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और प्रतिष्ठित प्रकाशनों के हालिया तथ्यों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ से वापसी का रास्ता फिलहाल धुंधला दिखाई दे रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचे और नेतृत्व पर किए गए करीब 900 हवाई हमलों से हुई। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु ने पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल दिए। आज, 26 मार्च 2026 तक, यह युद्ध एक ऐसे चरण में पहुँच गया है जहाँ कूटनीति और विनाश के बीच की रेखा बेहद पतली हो गई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, इजरायली रक्षा बलों ने तेहरान और इस्फ़हान प्रांतों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर 600 से अधिक हमले किए हैं। वहीं, ईरान ने अपनी 'अस्तित्व की लड़ाई' बताते हुए इजरायली शहरों और बहरीन, जॉर्डन व कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इस युद्ध का सबसे भयावह असर दुनिया की जेब पर पड़ रहा है। ईरान द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को आंशिक रूप से बंद करने और गैर-मैत्रीपूर्ण जहाजों पर शुल्क लगाने के फैसले ने वैश्विक व्यापार को पंगु बना दिया है। 'द गार्डियन' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में गैस की कीमतों में 30% और डीजल में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यह केवल ऊर्जा का संकट नहीं है, बल्कि खाद और परिवहन महंगा होने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। तेल की कीमतों

में उछाल ने महंगाई को उस स्तर पर पहुँचा दिया है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना मुश्किल हो रहा है।

वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन एक ओर '15-सूत्रीय शांति योजना' की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर सैन्य दबाव को कम करने के मूड में नहीं दिख रहा है। ट्रंप का यह बयान कि ₹यदि कूटनीति विफल रही, तो बमबारी जारी रहेगी,₹ वार्ता की मेज पर बैठे मध्यस्थों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। ईरानी पक्ष में खामेनेई के बाद उपजे नेतृत्व के शून्य को भरने की कोशिशें तेज हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया है, जो यह दर्शाता है कि ईरान का कट्टरपंथी धड़ा अभी भी समझौते के पक्ष में नहीं है।

युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा; इसका खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। अल-होल जैसे शिविरों से हजारों कैदियों के भागने की खबरों ने 'इस्लामिक स्टेट' के पुनरुत्थान की आशंका को जन्म दे दिया है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा ईरानी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों ने इस युद्ध को यूरोप के दरवाजे तक पहुँचा दिया है। मध्य पूर्व के रिफ्यूजी कैंपों में दवाओं और भोजन की भारी कमी हो गई है, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बावजूद, युद्धरत पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तथ्यों की कसौटी पर परखें तो यह स्पष्ट है कि यह युद्ध केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पश्चिम एशिया के पुनर्गठन की एक खतरनाक कोशिश है। यदि 27 मार्च की समय सीमा तक कोई ठोस युद्धविराम नहीं होता, तो दुनिया को एक दीर्घकालिक क्षेत्रीय अस्थिरता और अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के लिए तैयार रहना होगा। चीन और रूस की इस संघर्ष में भूमिका अभी भी सस्पेंस बनी हुई है, लेकिन उनके द्वारा ईरान को दी जा रही तकनीकी मदद ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी हैं। साइबर हमलों की एक नई लहर ने वैश्विक बैंकिंग प्रणालियों को भी प्रभावित किया है, जिसे इस युद्ध के 'डिजिटल फ्रंट' के रूप में देखा जा रहा है।

इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे समाप्त करना और उसके बाद के 'सुरक्षा शून्य' को भरना सबसे कठिन कार्य होता है। आज दुनिया केवल पश्चिम एशिया की आग नहीं देख रही, बल्कि अपनी रसोई और गाड़ी के ईंधन के माध्यम से इस युद्ध की कीमत चुका रही है। आने वाले कुछ दिन वैश्विक राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे। क्या विश्व नेतृत्व इस आग को बुझाने में सफल होगा या हम एक और विनाशकारी वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? यह सवाल आज हर उस व्यक्ति के जहन में है जो शांति और स्थिरता का पक्षधर है।

अंततः, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझना होगा कि सैन्य जीत कभी भी स्थायी शांति का विकल्प नहीं हो सकती। कूटनीतिक रास्तों को बंद करना केवल विनाश को आमंत्रण देना है। ईरान-अमेरिका के इस टकराव ने यह साबित कर दिया है कि आज की वैश्वीकृत दुनिया में कोई भी युद्ध स्थानीय नहीं रह जाता। इसकी लहरें हर महाद्वीप तक पहुँचती हैं और हर नागरिक को प्रभावित करती हैं। समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस रक्तपात को रोकें, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।

हमारी गीता

अर्जुन के मन का द्वंद्व

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

बच्चा गलती करता है और उसे डांट-फटकार मिलती है, तो वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। परंतु यहां भगवान के चाबुक जैसे कठोर वचनों के बाद भी अर्जुन अपना कहना, रोना-धोना छोड़ नहीं पा रहे हैं—यह विशेष है। इसका उत्तर भी उनके ही प्रश्नों और तर्कों में छिपा हुआ है। अर्जुन कहते हैं, "हे मधुसूदन! जो पूजनीय हैं, ऐसे भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य—मैं उनके साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं?" बचपन से जिन्होंने उनका पालन-पोषण किया, संस्कार दिए, वे भीष्म पितामह हैं; और द्रोणाचार्य तो उनके गुरु हैं। अर्जुन ने समस्त धनुर्विद्या उन्हीं से सीखी थी। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से भी अधिक शिक्षा अर्जुन को दी थी। छोटे-छोटे हाथों में धनुष पकड़ना भी उन्होंने ही सिखाया था। सरल मन के अर्जुन के लिए ये दोनों अत्यंत प्रिय और आदरणीय थे। वे उनकी पूजा करते थे। अर्जुन को धर्म का ज्ञान है। वे अधर्म करना नहीं चाहते। यदि यह धर्म-अधर्म या नीति-अनीति का प्रश्न होता, तो निस्संदेह अर्जुन ही नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति धर्म का ही पक्ष लेता। परंतु यहां समस्या यह है कि दोनों ही पक्ष अपने-अपने स्थान पर उचित प्रतीत होते हैं। ऐसे में कौन-सा धर्म चुना जाए? अर्जुन इसी धर्म-संशय में पड़ गए हैं। एक ओर पूजनीय गुरु और पितामह का आदर करना उनका धर्म है, और दूसरी ओर क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना भी उनका धर्म है। बाहर का युद्ध जितना भयंकर है, उससे

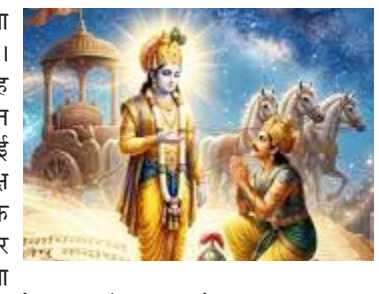

कहीं अधिक बड़ा संघर्ष अर्जुन के मन में चल रहा है। दोनों ही धर्म हैं—अब किसे निभाया जाए?

द्वंद्व ही हमारे जीवन का सत्य है। "होना या न होना"—यही प्रश्न हर मोड़ पर खड़ा रहता है। जैसे ही बचपन समाप्त होता है और जीवन के निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं, मन इसी द्वंद्व में उलझ जाता है। दसवीं के बाद—विज्ञान या वाणिज्य? कौन-सी शाखा, कौन-सा महाविद्यालय? नौकरी या व्यवसाय? यह लड़की या वह? विवाह के बाद—मां की सुनें या पत्नी की? सभी मार्ग अच्छे प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें से एक ही चुनना होता है।

शख्सियत

क्रांति का मौन साधक

बटुकेश्वर दत्त

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जब भी इंक़लाब का नारा गूंजता है, तो बरबस ही शहीद भगत सिंह का चेहरा सामने आता है। लेकिन उसी इंक़ालाबी गूंज के पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व भी था, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर मौत को चुनौती दी, पर इतिहास के पन्नों में उसे वह स्थान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। वह महान क्रांतिकारी थे— बटुकेश्वर दत्त। 27 मार्च को उनकी जयंती पर उनके संघर्षमय जीवन का स्मरण करना हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

बटुकेश्वर दत्त का जन्म 27 मार्च, 1910 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा कानपुर में हुई, जहाँ उनकी मुलाकात भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे राष्ट्रभक्तों से हुई। देश प्रेम का जज्बा उनके भीतर बचपन से ही था, लेकिन 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) से जुड़ने के बाद उनके जीवन को एक निश्चित दिशा मिली। वे एक कुशल बम निर्माता थे और संगठन के अत्यंत विश्वसनीय सदस्य माने जाते थे।

8 अप्रैल, 1929 का दिन भारतीय इतिहास का वह मोड़ था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। अंग्रेज सरकार 'पब्लिक सेफ्टी बिल' और 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' जैसे दमनकारी कानून लाकर भारतीयों की आवाज़ कुचलना चाहती थी। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे सोती हुई सरकार को जगाएंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि ₹इंक़लाब ज़िंदाबाद₹ के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। बटुकेश्वर दत्त की शांत और अडिग मुद्रा ने उस समय पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

गिरफ्तारी के बाद बटुकेश्वर दत्त को 'काला पानी' (सेल्युलर जेल, अंडमान) भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने जो यातनाएं झेलीं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। जेल में राजनीतिक कैदियों को इंसान नहीं समझा जाता था। इसके विरोध में उन्होंने जेल के भीतर ही लंबी भूख हड़ताल की। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई दिनों तक बिना अन्न-जल के रहने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके।

विडंबना देखिए कि जिस क्रांतिकारी ने देश की आजादी के लिए अपनी जवानी जेल की सलाखों के पीछे काट दी, उसे आजाद भारत में घोर अभावों का सामना करना पड़ा। 1947 के बाद जब वे जेल से छूटे, तो उनके पास न रहने को घर था और न ही आय का कोई साधन। एक समय ऐसा भी आया जब इस महान सेनानी को अपना गुजारा करने के लिए बिस्कुट कारखाने में काम करना पड़ा और बसें चलानी पड़ीं। यह हमारे इतिहास का एक दुखद अध्याय है कि जिस व्यक्ति ने असेंबली में बम फेंककर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, उसे स्वतंत्र भारत में अपनी पहचान साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि, उनके चेहरे पर कभी कोई शिकवा नहीं था। वे अंत तक उसी सादगी और स्वाभिमान के साथ जिए, जो एक सच्चे क्रांतिकारी की पहचान होती है।

20 जुलाई, 1965 को बटुकेश्वर दत्त ने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाए जहाँ उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का किया गया था। आज हुसैनीवाला में उनकी समाधि हमें याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। बटुकेश्वर दत्त का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र सेवा के लिए केवल जोश ही नहीं, बल्कि अपार धैर्य और त्याग की भी आवश्यकता होती है।

जीवन ऊर्जा

विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगन जर्मनी के महान भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 27 मार्च 1845 को हुआ था। उन्होंने 1895 में एक्स-रे (X-Ray) की खोज की, जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। उनकी इस खोज से बिना शरीर को काटे अंदर की हड्डियों और अंगों को देखना संभव हो गया। उनका निधन 10 फरवरी 1923 को जर्मनी में हुआ।

विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगन : जन्म : 27 मार्च 1845

जन्म

ज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा है

मैंने खोज नहीं की, मैंने केवल उसे पाया जो पहले से मौजूद था। विज्ञान में सबसे बड़ा आनंद नई चीजों को समझने में है। जिज्ञासा ही हर खोज की शुरुआत होती है। सच्चा वैज्ञानिक सत्य की खोज में लगा रहता है। ज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा है। प्रकृति अपने रहस्य उन पर खोलती है जो धैर्य रखते हैं। हर खोज एक नए प्रश्न को जन्म देती है। विज्ञान में विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अनुसंधान धैर्य और विश्वास का परिणाम है। सत्य की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। विज्ञान में कल्पना भी उतनी ही जरूरी है जितनी तर्क। नई खोजें दुनिया को बदल देती

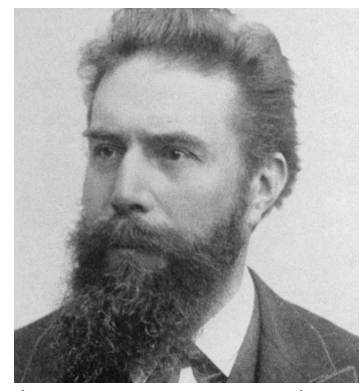

हैं। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। हर असफलता एक नई सीख देती है। विज्ञान सीमाओं को नहीं मानता। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्रकृति का अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। समर्पण से ही महान कार्य होते हैं। छोटे-छोटे प्रयास बड़े परिणाम देते हैं। विज्ञान मानवता का सबसे बड़ा मित्र है। हर खोज मानव जीवन को सरल बनाती है। सवाल पूछना ही समझ की शुरुआत है। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। धैर्य से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। विज्ञान में कोई अंतिम सीमा नहीं है। जिज्ञासा को कभी खत्म न होने दें। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है। हर प्रयोग एक नई दिशा दिखाता है। सत्य हमेशा खोजने वालों को मिलता है। विज्ञान का मार्ग कठिन लेकिन महान है। प्रकृति के नियम अटल हैं। समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। विज्ञान जीवन को बेहतर बनाता है। नवाचार ही प्रगति का आधार है।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

भक्ति, विश्वास और नाम-महिमा की अद्भुत कथा

भारतीय अध्यात्म में यह मान्यता गहराई से स्थापित है कि ईश्वर के नाम में अपार शक्ति होती है। इसी सत्य को उजागर करने वाली एक प्रेरक कथा राजा सुकंत, महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद, माता अंजनी और श्रीहनुमान से जुड़ी है, जो बताती है कि संकट की घड़ी में नाम-स्मरण कैसे रक्षा कवच बन जाता है।

एक समय की बात है, सुकंत नामक एक प्रतापी राजा भगवान श्रीराम के दरबार में दर्शन हेतु जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उनसे कहा कि सभा में अनेक ब्रह्मर्षि उपस्थित होंगे, अतः सबको प्रणाम अवश्य करना। परंतु उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि विश्वामित्र को केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना, चरण स्पर्श न करना। सुकंत ने संकोच के साथ उनकी बात मान ली।

दरबार में सुकंत ने भगवान श्रीराम को नमन किया और सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक झुकाया, परंतु विश्वामित्र को केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय तो विश्वामित्र ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु बाद में नारद जी ने उन्हें यह कहकर उकसाया कि सुकंत ने उनका अपमान किया है और उन्हें क्षत्रिय मूल का बताकर पूर्ण सम्मान नहीं दिया। यह सुनते ही विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्रीराम से कहा कि सूर्यास्त से पहले सुकंत का मस्तक उनके चरणों में होना चाहिए।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने गुरु आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। उधर नारद जी सुकंत के पास पहुंचे और उन्हें संकट की

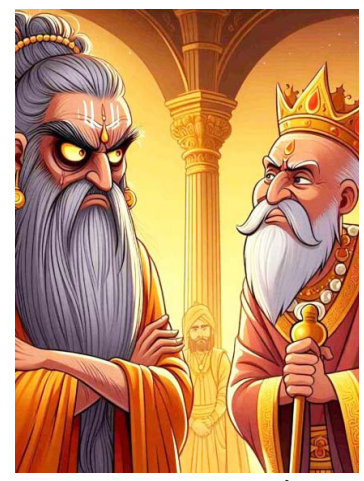

सूचना दी। भयभीत सुकंत ने रक्षा का उपाय पूछा। तब नारद जी उन्हें माता अंजनी के पास ले गए। माता ने अपने पुत्र हनुमान को आदेश दिया कि वे सुकंत की रक्षा करें। हनुमान जी धर्मसंकट में पड़ गए—एक ओर प्रभु श्रीराम की आज्ञा, दूसरी ओर माता का वचन। अंततः उन्होंने एक उपाय बताया—निरंतर राम नाम का जप।

सुकंत ने बैठकर अखंड जप प्रारंभ किया—सीताराम, सीताराम। हनुमान जी भी उनके साथ कीर्तन करने लगे। उसी समय श्रीराम का अमोघ बाण छोड़ा गया, परंतु जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, जहाँ नाम-स्मरण हो रहा था, वह रुक गया और वापस लौट आया। यह अद्भुत घटना थी—अमोघ बाण भी निष्फल हो गया।

जब श्रीराम स्वयं वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुकंत, हनुमान और लक्ष्मण सभी राम नाम में लीन हैं। श्रीराम ने करुणा से कहा कि जिस स्थान पर निरंतर मेरा नाम गूंजता है, वहां मेरा बाण भी प्रभाव नहीं डाल सकता। उन्होंने सुकंत से कहा कि वे अपना मस्तक विश्वामित्र के चरणों में रख दें, इस प्रकार गुरु आज्ञा भी पूर्ण हो गई और सुकंत की रक्षा भी हो गई।

तब नारद जी ने मुस्कराकर कहा कि उनका उद्देश्य यही दिखाना था कि भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान से भी बढ़कर है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया नाम-स्मरण हर संकट को टाल सकता है। जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराने के बजाय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। नाम में ऐसी शक्ति है, जो असंभव को संभव बना देती है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

दिल्ली में 11 साल तक आम आमदी पार्टी की सरकार रही और केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान दिल्ली में भी डकैती हुई। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सपना दिखाया, लेकिन उनका सारा पैसा लूट लिया और पैसे लूटकर अपने घर में लगाया। उनके घर में लगने वाली चीजों के लिए को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के खरीदा था और हर सामान की वैल्यू से ज्यादा पैसे अदा किए गए।

-प्रवेश वर्मा
मंत्री, दिल्ली सरकार

नीतीश कुमार के कार्यों को बुकलेट के माध्यम से घर-घर पहुंचाएं। विशेष रूप से वर्ष 2005 के बाद बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि जनता इन बदलावों से भलीभांति अवगत हो सके।

-निशांत कुमार
जदयू नेता

वह लगातार यह कहते रहे हैं कि भारत को अपने कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करवानी चाहिए। अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है, तो उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। मैं करीब तीन हफ्तों से कह रहा हूं कि भारत को आगे बढ़कर अपनी अच्छी कूटनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करना चाहिए था।

-शशि थरूर
कांग्रेस सांसद

धुरंधर' जैसी फिल्म इसलिए बनती हैं, क्योंकि इन्हें कोई फाइनेंस और फंडिंग करता है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कौन बना रहा, कौन नहीं। उन्होने एक लाइन लिख दी कि फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं। जब फिल्म बनाने वाला ही कह रहा सब काल्पनिक है, तो उसे सच क्या मानना।

-अखिलेश यादव
अध्यक्ष, सपा

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

हनुमान नगर में माता की चौकी, भक्ति के सागर में डूबे श्रद्धालु

नवी मुंबई। तुर्भे स्थित हनुमान नगर में सोमवार शाम पूनम सिंह स्थानीय महिला संगठन द्वारा आयोजित 'माता की चौकी' से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस विशेष कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक हीरा हमराही ने अपनी सुमधुर आवाज और 'पचरा' गीतों के माध्यम से माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का ऐसा मनमोहक वर्णन किया कि उपस्थित सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस आध्यात्मिक आयोजन में नगरसेवक अमित मेढ़कर, राजेश राय, अरविंद उपाध्याय और सूर्यनाथ परदेसी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और माता के जयकारों के बीच भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई। भारी संख्या में उमड़े भक्तों के उत्साह और कर्णप्रिय देवी गीतों ने पूरे हनुमान नगर को श्रद्धा और उल्लास के अनूठे संगम में सराबोर कर दिया।

महाष्टमी पर माता माई रजाइन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़

उल्हासनगर। उल्हासनगर-5 स्थित माता माई रजाइन मंदिर में महाष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहाँ मंदिर की भव्य सजावट और दीपों की रोशनी ने पूरे परिसर को जगमग कर दिया। इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कुमार आयलानी और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वधर्या ने माता के दरबार में हाजिरी लगाकर शहर की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की। पूर्व नगरसेवक किशोर वनवारी द्वारा आयोजित इस विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में उपमहापौर अमर लुंड, प्रदीप रामचंदानी और सुनीता विलास काकडे सहित कई गणमान्य नेताओं और भारी संख्या में स्थानीय भक्तों ने सहभागिता की। माता के जयकारों से गूंजते मंदिर परिसर में भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

मुंबई-मॉस्को 'दोस्ती' से बदलेगी एमएमआर की सूरत

एमएमआरडीए–मॉस्को सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता

मेट्रो, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं में मिलेगी रूसी तकनीक

> मॉस्को सरकार के साथ यह साझेदारी महाराष्ट्र के बढ़ते वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। इससे विश्वस्तरीय और भविष्य के लिए तैयार शहरों के निर्माण के हमारे प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। मुंबई केवल भारत की आर्थिक राजधानी नहीं, बल्कि वैश्विक विकास का केंद्र है और ऐसे सहयोग से एमएमआर को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी आएगी।
> **– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री**

> यह समझौता मुंबई के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक अनुभव का उपयोग करते हुए हम विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक, सुलभ और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे का निर्माण हमारी प्राथमिकता है।
> **– एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री**

दीपक पवार । मुंबई

रामनवमी के शुभ अवसर पर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग और रूस की मॉस्को सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और सतत शहरी विकास को गति देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

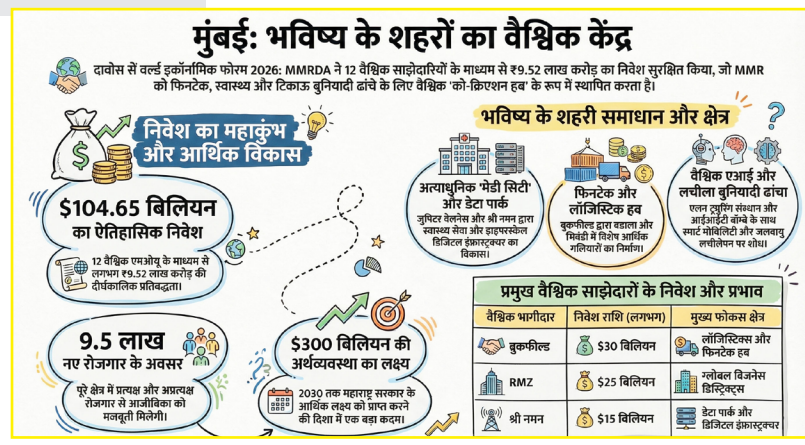

एमएमआरडीए की अहम भूमिका

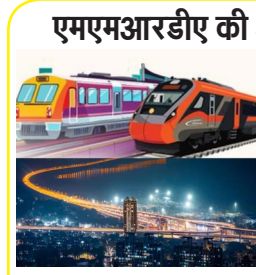

1974 के अधिनियम के तहत स्थापित एमएमआरडीए 6,328 वर्ग किलोमीटर में फैले मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र भारत के जीडीपी में करीब 5 से 6 प्रतिशत का योगदान देता है। 337 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क और अटल सेतु जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए एमएमआर को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा रहा है।

कई क्षेत्रों में सहयोग का रोडमैप तैयार

इस समझौते के तहत शहरी बुनियादी ढांचा, नवाचार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही नीति समन्वय, ज्ञान साझा करना और क्षमता विकास पर विशेष जोर रहेगा।

मुंबई को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में कदम

इस साझेदारी से मुंबई को एक मजबूत वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। विश्वस्तरीय तकनीक, योजना और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाकर मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समझौता

इस MoU पर एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी और मॉस्को सरकार के मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुंबई में रूसी संघ के महावाणिज्य दूत इवान फेटिसोव भी उपस्थित रहे।

2030 तक 300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

यह समझौता नीति आयोग की उस योजना के अनुरूप है, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र को 300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2030 तक लगभग 30 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

ठाणे मनोरुग्णालय की कोशिशों ने रंग दिखाया

4 महीने से लापता भाई दिल्ली के परिवार से मिला

मरीन ड्राइव पर मिला था मानसिक रूप से परेशान युवक

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

प्रादेशिक मनोरुग्णालय से मानवता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने दिल्ली में रह रहे एक परिवार की चार महीने पुरानी मायूसी को खुशियों में बदल दिया। बिहार के छपरा जिले का रहने वाला एक युवक, जो मायानगरी मुंबई की भीड़ में कहीं खो गया था, अस्पताल के डॉक्टरों और सोशल सर्विस विभाग की ज़िद के कारण अपने भाई से दोबारा मिल सका। 7 नवंबर 2025 को मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक युवक अत्यंत दयनीय और मानसिक रूप से परेशान हालत में मिला था। पुलिस ने उसे तुरंत ठाणे के मनोरुग्णालय में भर्ती कराया। शुरुआत में युवक पूरी तरह खामोश था और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. नेताजी मुलिक की देखरेख में उसका इलाज शुरू हुआ।

सोशल मीडिया का कमाल

अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने मरीज़ के साथ लगातार बातचीत की और उसे सहज महसूस कराया। कुछ दिनों के इलाज के बाद युवक ने अपना नाम सुरेंद्र शर्मा (बदला हुआ नाम) और अपना घर बिहार के छपरा जिले में बताया। यहीं से तलाश का दूसरा दौर शुरू हुआ। सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट सतीश वाघ ने तुरंत बिहार की दाउदपुर पुलिस से संपर्क साधा। जांच में पता चला कि परिवार अब छपरा में नहीं बल्कि दिल्ली में रहता है। पुलिस ने युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसे देखकर एक स्थानीय व्यक्ति ने उसके भाई रितेश का नंबर पुलिस को दिया।

वीडियो कॉल पर हुई पहली पहचान

13 जनवरी 2026 को वीडियो कॉल के ज़रिए रितेश ने अपने भाई को पहचान लिया। हालांकि, डॉक्टर जल्दबाज़ी में नहीं थे। उन्होंने तय किया कि जब तक सुरेंद्र मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, उसे परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। इस दौरान अस्पताल की नर्सों और काउंसलिंग टीम ने उसे जबरदस्त साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। हाल ही में जब सुरेंद्र पूरी तरह ठीक हो गया, तो भाई रितेश उसे लेने ठाणे अस्पताल पहुँचा। दोनों भाइयों को गले मिलते देख अस्पताल का स्टाफ भी भावुक हो गया। रितेश ने अस्पताल प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उनके परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है।

4 विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ी

78 अतिरिक्त सेवाएं चलेंगी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेल ने चार विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत कुल 78 अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

बीकानेर–शिर्डी विशेष ट्रेन का विस्तार

ट्रेन संख्या 04715 बीकानेर–साईनगर शिर्डी साप्ताहिक विशेष, जो पहले 28 मार्च 2026 तक चलने वाली थी, अब 11 जुलाई 2026 तक हर शनिवार चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04716 साईनगर शिर्डी–बीकानेर विशेष, जो 29 मार्च 2026 तक निर्धारित थी, अब 12 जुलाई 2026 तक हर रविवार संचालित होगी। इन दोनों ट्रेनों के कुल 30 अतिरिक्त फेरे (15-15) लगाए जाएंगे।

अजमेर–दौंड मार्ग पर अतिरिक्त सेवाएं

ट्रेन संख्या 09625 अजमेर–दौंड साप्ताहिक विशेष, जो 26 मार्च 2026 तक निर्धारित थी, अब 23 अप्रैल 2026 तक हर गुरुवार चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09626 दौंड–अजमेर विशेष को 24 अप्रैल 2026 तक हर शुक्रवार के लिए बढ़ाया गया है। इन ट्रेनों के कुल 8 अतिरिक्त फेरे (4-4) संचालित होंगे।

हिसार–खड़की विशेष ट्रेन को मिला विस्तार

ट्रेन संख्या 04725 हिसार–खड़की साप्ताहिक विशेष, जो 29 मार्च 2026 तक चलनी थी, अब 26 अप्रैल 2026 तक हर रविवार चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04726 खड़की–हिसार विशेष को 27 अप्रैल 2026 तक हर सोमवार के लिए बढ़ाया गया है। इन दोनों ट्रेनों के कुल 8 अतिरिक्त फेरे (4-4) निर्धारित किए गए हैं।

अजमेर–सोलापुर विशेष ट्रेन का लंबा विस्तार

ट्रेन संख्या 09627 अजमेर–सोलापुर साप्ताहिक विशेष, जो 25 मार्च 2026 तक चलनी थी, अब 15 जुलाई 2026 तक हर बुधवार संचालित होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09628 सोलापुर–अजमेर विशेष को 16 जुलाई 2026 तक हर गुरुवार के लिए बढ़ाया गया है।

पुराने और ऊंचे पेड़ों को ज़हर देकर मारने का आरोप

सरकार से 'ट्री-सेंट्रिक डिज़ाइन' की मांग

विकास की वेदी पर चढ़ती हरियाली

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

मुंबई और ठाणे में कंक्रीट के जंगलों के बीच सांस लेती हरियाली पर मंडराते संकट को लेकर पर्यावरणविद डॉ. प्रशांत रवींद्र सिनकर ने एक ज़ोरदार चेतावनी जारी की है। उन्होंने 'हाउसिंग प्रोजेक्ट्स' की आड़ में हो रही पेड़ों की सुनियोजित हत्या को विकास नहीं, बल्कि विनाश करार दिया है। डॉ. सिनकर ने आरोप लगाया है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स पुराने पेड़ों को रास्ते का रोड़ा मानकर उन्हें मारने के लिए क्रूर तरीके अपना रहे हैं। इसमें पेड़ों के तनों में ज़हरीले केमिकल डालना, जड़ों के चारों ओर कंक्रीट भरकर उनका दम घोंटना और रात के अंधेरे में चुपचाप पेड़ों को काटना शामिल है।

'अर्बन हीट आइलैंड' बनती मुंबई-ठाणे

पेड़ों की घटती संख्या और बढ़ती कंक्रीटिंग की वजह से ये शहर 'अर्बन हीट आइलैंड्स' में बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज़्यादा रहता है। इससे न केवल गर्मी बढ़ रही है, बल्कि वायु प्रदूषण (Air Pollution) के कारण लोगों में सांस की बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं।

बाढ़ का बढ़ता खतरा

पेड़ न होने की वजह से बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। नतीजतन, हल्की बारिश में भी सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। हरियाली ही पानी को सोखने का सबसे बड़ा प्राकृतिक माध्यम है।

ठाणे ट्रैफिक पुलिस बनी छात्रों की लाइफलाइन

46 बच्चों का साल बचाने वाले जांबाज राइडर्स

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान ठाणे ट्रैफिक पुलिस की 'राइडर्स' पहल ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। 10 फरवरी से 18 मार्च के बीच इस विशेष अभियान के जरिए 46 छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाकर उनका शैक्षणिक साल बचाया गया। ट्रैफिक जाम, गाड़ी खराब होने और लोकल ट्रेन की देरी जैसी समस्याओं के बीच यह पहल छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हुई।

राइडर्स और हेल्पलाइन से मिली तुरंत मदद

ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण के मार्गदर्शन में शुरू इस पहल के तहत 54 ट्रैफिक राइडर्स तैनात किए गए थे। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और WhatsApp सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जिससे पेरेंट्स और छात्रों को तुरंत सहायता मिल सकी। पहले ही दिन कंट्रोल रूम को 25 कॉल्स प्राप्त हुए, जो इस पहल की जरूरत और प्रभाव को दर्शाता है।

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाए परीक्षा केंद्र

कई मौकों पर ट्रैफिक राइडर्स ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 'ग्रीन कॉरिडोर' तैयार किया। 17 फरवरी को ट्रैफिक जाम में फंसे 4 छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया गया, जबकि 7 मार्च को अंबरनाथ के दो छात्रों को ट्रेन देरी के बावजूद वैकल्पिक मार्ग से कल्याण केंद्र तक पहुंचाकर उनका साल बचाया गया।

पुलिस की संवेदनशील पहल की सराहना

इस पहल की पेरेंट्स और नागरिकों ने सराहना की है। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट ने राइडर्स और पुलिसकर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सिर्फ ट्रैफिक प्रबंधन नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक संवेदनशील कदम है।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

प्रियंका जैन
97699 94439

मेष संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। संतान संबंधी चिंता कम होगी। स्वाभाविक सोच में बदलाव आएगा। रुका पैसा प्रयास करने पर प्राप्त होने के योग हैं। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा।

वृष मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। प्रमाद न करें। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना होगा। प्रतिस्पर्धा, शत्रुता से परेशानी संभव है। अनसोचे कामों में हाथ नहीं डालें।

मिथुन मेहमानों का आगमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। धनार्जन होगा। नियमित कर्ज, लेनदेन में कटौती करना होगी। योजनाओं पर चर्चा, कार्य के प्रति लगन रह पाएगी। नौकरी, राज्यपक्ष में स्थायित्व की बात आएगी।

कर्क यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ होगा। जोखिम न लें। बड़े व्यक्तियों से भेंट का लाभ मिलेगा। कानूनी कार्यों में समय सीमा का ध्यान रखें। व्यवहारकुशलता का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक श्रेष्ठता रहेगी।

सिंह कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। तंत्र-मंत्र में रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। शुभ समय। यात्रा में अपनी वस्तुओं को संभालकर रखें। पैतृक संपत्ति के क्षेत्रों में उन्नति होगी। नौकरी में संयत व्यवहार आवश्यक है।

कन्या रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। स्वादिष्ट भोजन भोजन का आनंद मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रसन्नता रहेगी। मनोविनोद के अवसर मिलेंगे। भाई-बहनों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक काम होंगे।

तुला व्यर्थ दौड़धूप रहेगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बुरी खबर मिल सकती है। चिंता रहेगी। मानसिक शांति रहेगी। व्यापारिक विवादों का आसान हल निकाल सकेंगे। वाणी पर संयम रखना चाहिए। अधीनस्थों से मदद मिलेगी।

वृश्चिक आकस्मिक खर्च अधिक होगा। तनाव रहेगा। थकान रहेगी। जोखिम न लें। धैर्य रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। संघर्ष, भागदौड़ के बाद रोजगार में इच्छित सफलता मिलने के योग हैं। परिवार, समाज में आपके कार्यों को महत्व दिया जाएगा।

धनु योजना फलीभूत होगी। कार्य की प्रशंसा होगी। आय में वृद्धि होगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रमाद न करें। संतान, भाइयों से लाभ होगा। घरेलू उपयोग की वस्तुएँ क्रय करेंगे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएँगे।

मकर राजकीय मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। सामान्य प्रतिष्ठा, सम्मान से उत्साहित रहेंगे। खर्चों में कमी का प्रयास करना होगा। व्यापार-व्यवसाय में विवेक से निर्णय लेने पर आशानुकूल लाभ के योग हैं।

कुंभ यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। जोखिम न लें। जल्दबाजी न करें। लेन-देन में सावधानी रखें। उच्चाधिकारियों से सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सकेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। पूँजी निवेश लाभदायी रहेगा।

मीन चोट, चोरी व विवाद से हानि संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। कुसंगति से बचें। थकान रहेगी। परिवार में आर्थिक समस्या को लेकर विचार-विमर्श होगा। दूसरों से अपमानजनक व्यवहार न करें। कार्यक्षेत्र में इच्छित सफलता व संतोष रहेगा।

धन, भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने का अचूक मार्ग

प्रियंका जैन
97699 94439

भारतीय परंपरा और वैदिक ज्योतिष में गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह दिन Lord Vishnu और Brihaspati को समर्पित होता है, जिन्हें देवताओं का गुरु और ज्ञान, धन तथा धर्म का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। साथ ही Goddess Lakshmi की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है।

गुरुवार केवल एक साधारण दिन नहीं, बल्कि यह वह अवसर है जब व्यक्ति अपनी किस्मत को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। यह दिन न केवल भौतिक सुख-संपदा देता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं गुरुवार के वे 5 अचूक उपाय, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है लक्ष्मी-विष्णु की पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ, विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ-सुथरा रखें और वहां Lord Vishnu और Goddess Lakshmi की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में तुलसी के पत्ते, पीले फूल, चंदन और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय न केवल धन की प्राप्ति के लिए, बल्कि आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

दूसरा उपाय है पीले रंग का विशेष उपयोग। गुरुवार का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, और पीला रंग इस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले फूलों से पूजा करना और भोजन में भी पीली चीजों का सेवन करना शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। कहा जाता है कि पीला रंग व्यक्ति के भाग्य को मजबूत करता है और जीवन में नई संभावनाएं लाता है।

तीसरा उपाय है केले के पेड़ की पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केला वृक्ष Brihaspati और Goddess Lakshmi का प्रतीक माना जाता है। गुरुवार की सुबह केले के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करें, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और पीले धागे से पेड़ को बांधें। इसके बाद श्रद्धा से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने और नए अवसरों को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है।

चौथा उपाय है दान-पुण्य करना। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दान के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी होता है। जैसे हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, केसर या पीली मिठाई किसी जरूरतमंद को दान करें। यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। यह कार्य न केवल आपके पापों को कम करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। दान से मन की शुद्धि होती है और Goddess Lakshmi की कृपा प्राप्त होती है।

मंत्री की नसीहतः ऐसे नहीं बढ़ेगी बनारस की शोभा

बिजली के लटकते तार और लकड़ी के पोल पर मंत्री नाराज

समीक्षा के दौरान विभागीय अफसरों को दी सुधार की हिदायत

एजेंसी । वाराणसी

धार्मिक और पर्यटन नगरी वाराणसी को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गुरुवार को सर्किट हाउस में नगर निगम और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर शहर की जमीनी समस्याओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वाराणसी देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों का रखें ध्यान

ऐसे में यहां की आधारभूत व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मंत्री ने विशेष रूप से शहर में जगह-जगह झूलते बिजली के तारों, जर्जर केबलों और अव्यवस्थित ट्रांसफार्मरों को गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम से पहले ही व्यापक अभियान चलाकर पुराने तारों को बदला जाए, अंडरग्राउंड केबलिंग को प्राथमिकता दी जाए और अस्थायी व्यवस्थाओं जैसे बांस-बल्ली की जगह स्थायी पोल लगाए जाएं। साथ ही, ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा और नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने को कहा, ताकि गर्मी में किसी भी प्रकार की बिजली संकट की स्थिति न बने। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर भी मंत्री ने सख्ती दिखाई।

ननि को कूड़ा प्रबंधन का पढ़ाया पाठ

उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया कि कूड़ा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए और सड़कों के किनारे पड़े मलबे को तत्काल हटाया जाए। प्रमुख तिराहों और चौराहों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के साथ ही सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। मंत्री ने घाटों की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिया कि यहां नियमित सफाई, कचरा निस्तारण और निगरानी की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

गली-मोहल्लों पर विशेष ध्यान दें अधिकारी

शहर के भीतरी इलाकों की समस्याओं पर ध्यान दिलाते हुए एके शर्मा ने कहा कि गली-मोहल्लों में नालियों और सीवर की नियमित सफाई के लिए जोन स्तर के अधिकारियों को फील्ड में उतरकर काम करना होगा। उन्होंने गोदौलिया, चौक और मैदागिन जैसे व्यस्त बाजार क्षेत्रों में कूड़ा उठान में किसी भी प्रकार की देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करें। बैठक में नगर आयुक्त, महापौर, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक समेत नगर निगम और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राम की चौखट पर दिग्गी राजा !

रामनवमी पर राम की नगरी पहुंचे दिग्विजय सिंह, किया दर्शन

राम मंदिर विरोध के सवाल पर कहा- कभी विरोध नहीं किया

एजेंसी । अयोध्या

रामनवमी के पावन अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को अयोध्या पहुंचे और श्रीरामलला के दरबार में मत्था टेककर देश की खुशहाली की कामना की। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण के विरोध से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनका रुख सदैव आस्था के पक्ष में रहा है। उनके इस दौरे को राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अयोध्या आना सौभाग्य की बात

महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर आगमन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन-पूजन किए। इसके साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी पूजा-अर्चना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन अयोध्या आना उनके लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कभी नहीं किया मंदिर का विरोध राम मंदिर के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी श्रद्धा स्वरूप 1 लाख 11 हजार रुपये का सहयोग भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनके विचारों को लेकर जो धारणा बनाई गई है, वह वास्तविकता से परे है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों या पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर टिप्पणी से उन्होंने इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि वे धार्मिक यात्रा पर हैं और इस अवसर पर राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। रामलला के दर्शन कर तृप्त हुई आत्मा दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें आत्मिक संतोष मिला और उन्होंने प्रभु से देश में सद्भाव, एकता और खुशहाली बनाए रखने की कामना की। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पूर्व में लगातार सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह, मंदिर निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं, जिससे उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

एक लाख लेकर पास कर रहे थे 70 लाख का बिल

रिश्वतखोरी का खेल बेनकाब, एक लाख घूस लेते जेई गिरफ्तार

एजेंसी । मीरजापुर

भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत मीरजापुर में एंटी करप्शन टीम ने सिंचाई विभाग के एक अवर अभियंता (जेई) को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई बाणसागर कॉलोनी स्थित आरोपी के आवास पर की गई, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

ठेकेदार के नोट सौंपते ही दबोचा, केस दर्ज

शिकायत के आधार पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। बुधवार दोपहर करीब एक बजे जैसे ही ठेकेदार ने आरोपी को उसके आवास पर केमिकल लगे नोट सौंपे, पहले से मौजूद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही दबोच लिया।

रिश्वत लेते आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तारी के दौरान टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौरसिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने से जुड़ा है और जारी है। गिरफ्तार जेई की पहचान मुसाफिर सिंह यादव के रूप में हुई है जो बाणसागर परियोजना खंड-पांच में तैनात था। आरोप है कि उसने प्रयागराज के मेजा निवासी ठेकेदार दीपक कुमार से करीब 70 लाख रुपये का बिल पास कराने के एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

उग्र भीड़ ने थानेदार समेत पुलिस टीम को पीटा

एजेंसी । सुपौल

बिहार के सुपौल जिले में देर रात छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला होने से हालात तनावपूर्ण हो गए। राघोपुर प्रखंड के करजाईन थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव में कार्रवाई के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष मनीष कुमार सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, शराब तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी सरोज कुमार मेहता की गिरफ्तारी के लिए टीम बुधवार रात गांव पहुंची थी।

अब मेटल डिटेक्टर से गुजरने पर भारत में मिलेगा प्रवेश

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी

दिघलबैंक चेकपोस्ट पर जांच हुई अनिवार्य

एजेंसी । किशनगंज

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से किशनगंज जिले के दिघलबैंक चेकपोस्ट पर निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब नेपाल से भारत आने वाले प्रत्येक यात्री को डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। के बाद सीमा पार आवागमन अब एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन जैसी सख्त सुरक्षा जांच के दायरे में आ गया है।

रोजाना गुजरते हैं सैकड़ों लोग

दिघलबैंक कंपनी के सहायक कमांडेंट प्रिय रंजन चकमा ने बताया कि अब हर व्यक्ति की मशीन के जरिए जांच के साथ पहचान सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चेकपोस्ट भारत और नेपाल के बीच आवागमन का प्रमुख मार्ग है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं, ऐसे में इसे संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए सुरक्षा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया गया है।

सामान की भी होगी प्रभावी तलाशी

गौरतलब है कि इस सीमा मार्ग का उपयोग दोनों देशों के नागरिक रोजमर्रा की जरूरतों, व्यापार और चिकित्सा सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में करते हैं। नई सुरक्षा व्यवस्था लागू होने के बाद अब यात्रियों की तलाशी और सामान की जांच अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी, जिससे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियों ने चेकपोस्ट पर वॉक-थ्रू मेटल डिटेक्टर गेट स्थापित कर दिया है।

टोल टैक्सः एक अप्रैल से नहीं चलेगा कैश

टोल दरों में हो रही है बढ़ोतरी, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य

एजेंसी । कानपुर देहात

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही जनपद के बारा टोल प्लाजा पर एक अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही नकद भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और सभी लेन-देन डिजिटल माध्यम से ही होंगे।

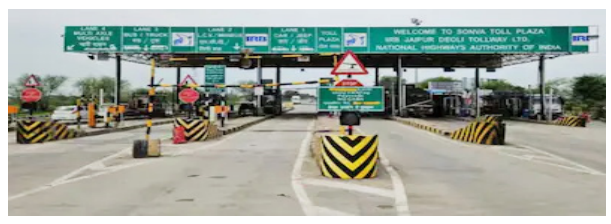

सिंगल जर्नी में पांच रुपये का इजाफा

नई दरों के तहत कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के सिंगल जर्नी टोल में 5 रुपये और रिटर्न जर्नी में 10 रुपये की वृद्धि की गई है। बारा टोल प्लाजा पर अब सिंगल यात्रा के लिए 190 रुपये और रिटर्न यात्रा के लिए 285 रुपये चुकाने होंगे, जो पहले क्रमशः 185 और 275 रुपये थे। वहीं, 20 किलोमीटर दायरे के लिए जारी होने वाले मंथली पास की फीस भी 350 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दी गई है।

यूपीआई से करना होगा भुगतान

टोल प्लाजा पर अब बिना फास्टैग या निष्क्रिय फास्टैग वाले वाहन चालकों के लिए नकद भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में वाहन चालकों को यूपीआई या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही भुगतान करना होगा। टोल बूथों पर क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान की सुविधा दी गई है, हालांकि इस स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ अतिरिक्त पेनाल्टी भी देनी होगी। इसके अलावा, 200 फेरों वाले सालाना पास की फीस भी 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है। अन्य श्रेणियों में भी टोल दरों में आंशिक बढ़ोतरी की गई है। लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए सिंगल जर्नी का शुल्क 290 से बढ़कर 295 रुपये और रिटर्न जर्नी का शुल्क 435 से बढ़कर 445 रुपये हो जाएगा। बस और ट्रक के लिए सिंगल जर्नी 605 रुपये तथा रिटर्न 910 रुपये तय किया गया है। ओवरसाइज वाहनों के लिए सिंगल जर्नी 1180 रुपये और रिटर्न जर्नी 1770 रुपये निर्धारित की गई है।

बिलासपुर में बर्ड फ्लू का कहर, हजारों पक्षी नष्ट

लापरवाही से बढ़ा संक्रमण का खतरा, सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल

एजेंसी । बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने आपात कदम उठाते हुए हजारों मुर्गियों और अंडों को नष्ट कराया है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई गंभीर लापरवाहियों ने संक्रमण के खतरे को और बढ़ा दिया है।

हजारों पक्षियों-अंडों को किया नष्ट

जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद करीब 22 हजार से अधिक पक्षियों और 25 हजार से ज्यादा अंडों को नष्ट किया गया है। इसके अलावा 79 क्विंटल चारा और हैचरी से जुड़ी सामग्री भी खत्म कर दी गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर दायरे को संक्रमित क्षेत्र और 10 किलोमीटर तक के इलाके को निगरानी जोन घोषित करते हुए पक्षियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद दो बड़ी चूकें सामने आई हैं। पहली, खमतराई इलाके में मरी हुई मुर्गियों को खुले में फेंकने का मामला, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। दूसरी, पक्षियों की मौत के बावजूद विभिन्न जिलों में चूजों और अंडों की सप्लाई जारी रहना। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

व्यापार जगत

6,967 पेट्रोल पंपों पर बढ़े ईंधन के भाव

नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पांच और डीजल तीन रुपये महंगा किया

सरकारी समेत अन्य पेट्रो कंपनियों के रेट में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर अब देश के ईंधन बाजार पर दिखने लगा है। इसी क्रम में नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी।

कच्चे तेल की कीमतों में 50% का उछाल

सूत्रों के मुताबिक, 28 फरवरी के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50 फीसदी तक उछाल आया है, जिसके चलते निजी ईंधन कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ी है। नायरा एनर्जी, जो देशभर में हजारों पेट्रोल पंप संचालित करती है, ने इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। हालांकि सरकारी कंपनियां अब तक खुद लागत वहन करते हुए खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं।

राज्यस्तर पर अलग-अलग होगी कीमत

बाजार के जानकारों का कहना है कि ईंधन कीमतों में यह बढ़ोतरी राज्यवार कर ढांचे के कारण अलग-अलग स्तर पर दिखेगी और कुछ स्थानों पर पेट्रोल 5.30 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। निजी कंपनियों का तर्क है कि उन्हें कीमतें नियंत्रित रखने पर किसी तरह का सरकारी मुआवजा नहीं मिलता, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नीति समर्थन हासिल रहता है।

वैश्विक तनाव के कारण बढ़ गई लागत

उधर, वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित होने और खाड़ी क्षेत्र में तनाव के चलते तेल परिवहन पर भी असर पड़ा है, जिससे लागत और बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी नहीं आई, तो अन्य कंपनियां भी ईंधन दरों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ डाल सकती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और BP Plc के ज्वाइंट फ्यूल रिटेल वेंचर, Jio-bp—जिसके 2,185 आउटलेट हैं, ने अपने पेट्रोल पंपों पर कीमते नहीं बढ़ाई हैं। रिलायंस को भी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी

हवाई सफर महंगा होने के आसार, सरकार से राहत की उम्मीद

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजार में जेट फ्यूल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल ने विमानन क्षेत्र पर दबाव बढ़ा दिया है। पिछले एक महीने में एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम 100 फीसदी से अधिक बढ़कर लगभग दोगुने हो गए हैं, जिससे हवाई किराए में तेज बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेट फ्यूल की कीमत करीब 95.90 डॉलर प्रति बैरल थी।

टैक्स में राहत देने की मांग

बढ़ती लागत से जूझ रही एयरलाइंस कंपनियों ने केंद्र सरकार से एयरपोर्ट चार्ज में कटौती और टैक्स में राहत देने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि यदि राहत नहीं मिली, तो उन्हें हवाई किराए में बड़ी वृद्धि करनी पड़ सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि निजी कंपनियों द्वारा संचालित अधिकांश हवाई अड्डों के चलते लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कटौती की संभावना सीमित है।

एयरस्पेस बंद होने से बढ़ी दूरी

इस बीच, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कई देशों के एयरस्पेस बंद होने से उड़ानों को लंबा रूट अपनाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत और लागत दोनों बढ़ गई हैं। ऐसे हालात में भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अप्रैल में एटीएफ कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर सीधे तौर पर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। इस उछाल का सीधा असर एयरलाइंस की परिचालन लागत पर पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी विमानन कंपनी के कुल खर्च में जेट फ्यूल की हिस्सेदारी लगभग 40 फीसदी तक होती है।

स्वास्थ्य बीमाः प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ पार

बीमा में 9% की तेज बढ़त, क्लेम निपटान के लिए सख्त समय-सीमा लागू

एजेंसी । नई दिल्ली

देश का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस सेक्टर ने करीब 9 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है। बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, व्यापक कवरेज और बेहतर इस वृद्धि को गति दी है। पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए सख्त समय-सीमाएं तय की हैं।

क्लेम सेटलमेंट में सुधार से बढ़ी रफ्तार

मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें पॉलिसीधारकों की बढ़ती उम्र, अधिक कवरेज विकल्प और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रमुख हैं। साथ ही, क्लेम सेटलमेंट में भी सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2022-23 में जहां 85.66 फीसदी दावों का भुगतान हुआ, वहीं 2023-24 में यह 82.46 फीसदी और 2024-25 में बढ़कर 87.50 फीसदी तक पहुंच गया।

बीमा से जुड़ी 1,37,361 शिकायतें आईं

इसके अलावा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के 'बीमा भरोसा' पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में सामान्य और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी 1,37,361 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 93 फीसदी यानी 1,27,755 शिकायतों का निपटारा इसी अवधि में कर दिया गया। सरकार का मानना है कि नियामकीय सख्ती और डिजिटल व्यवस्थाओं के विस्तार से बीमा क्षेत्र में भरोसा और दक्षता दोनों बढ़ रही हैं। कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन एक घंटे के भीतर और फाइनल ऑथराइजेशन तीन घंटे के अंदर पूरा करना अनिवार्य किया गया है, ताकि मरीजों को इलाज में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

देश में पेट्रो उत्पादों का कोई संकट नहीः सरकार

ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार सख्त, मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति

एजेंसी । नई दिल्ली

देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य होने का दावा किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देशभर में ईंधन की आपूर्ति सुचारु है और सभी पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।

एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप सक्रिय

मंत्रालय के अनुसार, देश में एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं और कहीं भी राशनिंग जैसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है। साथ ही किसी भी पंप को सप्लाई सीमित करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि आवश्यक वस्तुओं को लेकर झूठी जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवां सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक है, जो 150 से अधिक देशों को ईंधन आपूर्ति करता है।

देश के पास 60 दिन का पर्याप्त स्टाक

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में करीब 60 दिनों का पर्याप्त ईंधन स्टॉक मौजूद है, जबकि कुल भंडारण क्षमता 74 दिनों तक की है। एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने स्थिति को संतोषजनक बताया है। उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है। मंत्रालय ने दोहराया कि देश में किसी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान वैश्विक तनाव के बावजूद भारत को 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति मिल रही है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से संचालित हो रही हैं।

आरबीआई ने जारी किया एमपीसी कैलेंडर

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों का कैलेंडर जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक 6 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित होगी, जिसमें महंगाई, ब्याज दर और तरलता से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी पूरे वित्त वर्ष में कुल छह बैठकें करेगी। यह कैलेंडर आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय बैंक को पहले से नीतिगत बैठकों का कार्यक्रम सार्वजनिक करना होता है।

बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल के दूसरे चरण का कार्यक्रम

- प्लेऑफ और फाइनल की तारीख का नहीं किया एलान
- दूसरे चरण में आठ डबल हेडर मैच होंगे
- 12 शहर करेंगे मुकाबलों की मेजबानी

एजेंसी । मुंबई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हालांकि, बोर्ड ने फिलहाल प्लेऑफ और फाइनल मैच की तारीख का एलान नहीं किया है। बीसीसीआई ने 70 लीग मैचों का कार्यक्रम घोषित किया है जो 24 मई तक चलेगा। आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होगी। बोर्ड ने पहले 20 मैचों का कार्यक्रम घोषित किया था और अब दूसरे चरण में बीसीसीआई ने लीग चरण के शेष 50 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। आईपीएल 2026 का कार्यक्रम दो भागों में जारी किया गया है। पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ था और अब लीग चरण के शेष 50 मैचों का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसका कारण पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। असम, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे चार मई को जारी होंगे।

खिताब बचाने उतरेगी आरसीबी

आरसीबी की टीम इस बार अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आरसीबी ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। आरसीबी के लिए राहत की बात यह है कि उसके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम को मुकाबले की मेजबानी करने की मंजूरी मिल गई है। आईपीएल 2026 का उद्घाटन मैच बंगलूरू में ही खेला जाएगा।

13 शहरों में होंगे मैच

बीसीसीआई ने पहले 12 अप्रैल तक के मैचों का कार्यक्रम जारी किया था और अब 13 अप्रैल से 24 मई तक का शेड्यूल बता दिया है। दूसरे चरण में 12 वेन्यू पर आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल 2026 में कुल 13 स्थानों पर मैच होंगे। दूसरे चरण में बंगलूरू, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में मुकाबले होंगे।

धर्मशाला में होंगे तीन मुकाबले

दूसरे चरण में आठ डबल हेडर मुकाबले होंगे जिसमें दोपहर के मैच भारतीय समयानुसार 3 :30 बजे से होंगे, जबकि शाम के मैच 7 :30 बजे से खेले जाएंगे। पहले चरण में चार डबल हेडर होने हैं। यानी इस बार कुल 12 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पंजाब किंग्स की टीम अपने होम मुकाबले न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी। इस दौरान धर्मशाला में तीन मैच खेले जाएंगे। दूसरी तरफ, राजस्थान की टीम चार मैच जयपुर में खेलेगी, जबकि गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने तीन होम मैच बंगलूरू और दो रायपुर में खेलेगी। बीसीसीआई ने बताया कि प्लेऑफ के वेन्यू की घोषणा बाद में की जाएगी। पहले चरण में गुवाहाटी भी आईपीएल मैचों की मेजबानी कर रहा है, लेकिन दूसरे चरण में वहां मैच नहीं होंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 13 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैदराबाद में होने वाले मैच से होगी।

भारतीय स्कीट निशानेबाजों के सामने कड़ी चुनौती

एजेंसी । कपटैंगियेर

भारत के स्कीट निशानेबाजों को शुक्रवार से शुरू होने वाले सत्र के पहले शॉटगन विश्व कप के पहले दिन कई दिग्गज खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनके लिए पदक जीतना आसान नहीं होगा। प्रतियोगिता में कई प्रमुख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

भारत के 12 शूटर

पहले दिन की शुरुआत पुरुष और महिला दोनों वर्ग में 75 निशानों के साथ होगी। बाकी 50 निशाने और फाइनल रविवार को होगा। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अधिकतम छह खिलाड़ियों को रखने का कोटा पूरा किया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में दो-दो ऐसे निशानेबाज हैं जो केवल रैंकिंग अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय टीम में ओलंपियन माहेश्वरी चौहान और दोनों बहनें दर्शना राठौर और यशस्वी राठौर हैं। अरीबा खान और मानसी रघुवंशी भी रैंकिंग अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।महिला वर्ग की स्टार खिलाड़ियों में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चिली की फ्रांसिस्का क्रोवेटो चादिद और विश्व चैंपियन अमेरिका की सामंथा सिमोंटन भी हैं।

ज्योतिरादित्य, मान पर निगाहें

भारत की उम्मीदें अनुभवी मान सिंह और परम्पल सिंह गुरोन के साथ-साथ ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया पर होंगी, जो सीनियर स्तर पर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदार्पण कर रहे हैं। पूर्व एशियाई चैंपियन मान सिंह तीन साल बाद वापसी कर रहे हैं, जबकि परम्पल ने आखिरी बार 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सुखबीर सिंह हरिका और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन हरमेहर सिंह लल्ली रैंकिंग अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ज्योतिरादित्य ने पिछले साल शिमकेंट एशियाई चैंपियनशिप में अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जूनियर कांस्य पदक जीता था और वह भारत के लिए सीनियर स्तर पर पदार्पण करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक होंगे। पुरुषों के वर्ग में 82 प्रतिभागी अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनमें डेनमार्क के 2025 के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एमिल केल्डगार्ड पीटरसन का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका के क्रिश्चियन इलियट, इटली के दो बार के ओलंपिक चैंपियन गैब्रिएल रोसेटी, टोक्यो ओलंपिक के रजत विजेता डेनमार्क के जेस्पर हैनसेन और कतर के पूर्व विश्व चैंपियन और एशियाई खेलों के चैंपियन मसूद सालेह अल-अथबा प्रतियोगिता में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं। पहली बार कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अंगद वीर सिंह बाजवा भी चुनौती पेश करेंगे। वह पिछले साल तक भारत की तरफ से खेल रहे थे। इटली की दो बार की ओलंपिक और विश्व चैंपियन डायना बाकोसी, अमेरिका की पूर्व विश्व चैंपियन दानिया जो विज्जी और कजाखस्तान की विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता असीम ओरिनबे भी चुनौती देंगी।

सबालेंका लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में, रायबाकिना से भिड़ेंगी

- क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की आर्यना ने अमेरिकी बैपटिस्ट को हराया तो एलेना ने जेसिका पेगुला को शिकस्त दी

एजेंसी । फ्लोरिडा

मियामी ओपन

गत चैंपियन और दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका लगातार दूसरी बार मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने बुधवार रात क्वार्टर फाइनल में हैली बैपटिस्ट को हरा दिया। अब उनका सामना एलेना रायबाकिना से होगा जिन्होंने जेसिका पेगुला को शिकस्त दी। बेलारूस की 27 वर्षीय सबालेंका ने अमेरिका की 24 वर्षीय युवा बैपटिस्ट पर लगातार सेट में 6-4, 6-4 से शानदार जीत दर्ज करते हुए मियामी ओपन के लगातार दूसरे सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब वह अपने लगातार दूसरे खिताब से बस दो जीत दूर हैं। बैपटिस्ट ने सबलेंका को कड़ी टक्कर दी, लेकिन विश्व नंबर एक ने अपनी खास आक्रामक शैली बरकरार रखते हुए धीरे-धीरे मैच को अपने पक्ष में कर लिया।फाइनल में जगह बनाने के लिए सबालेंका का एलेना रायबाकिना के साथ 17वां मुकाबला होगा।

लगातार पांचवीं जीत

दूसरी ओर, तीसरी वरीय कजाखस्तान की 26 वर्षीय रायबाकिना ने पांचवीं वरीय 32 वर्षीय जेसिका पेगुला को लगातार पांचवीं बार हराकर मियामी ओपन के तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। रायबाकिना ने पहला सेट हारने के बाद वापसी की और अंत में 2-6, 6-3, 6-4 से यह मुकाबला जीता। मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन और दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकीं रायबाकिना का यहां सेमीफाइनल में 2-0 का रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2023 में पेगुला को और फिर 2024 में विक्टोरिया अजारेंका को शिकस्त दी थी।

स्पेन के मुनोज बेंगलुरु एफसी के मुख्य कोच बने

एजेंसी । बेंगलुरु

बेंगलुरु एफसी ने स्पेन के पेप मुनोज को 2026-27 के सत्र के अंत तक के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया है। इस फुटबॉल क्लब ने गुरुवार को यह घोषणा की। मुनोज ने इससे पहले एफसी बार्सिलोना के युवा सेटअप में बार्सा अंडर-19 और बार्सिलोना बी के साथ काम किया है। इसके अलावा वह चीन की राष्ट्रीय टीम और वहां के दो क्लबों किंगदाओ हुआंगहाई और शेडोंग लुनेन्ग के भी कोच रह चुके हैं। इससे पहले वह कंबोडिया में प्रेह खान रीच स्वे रींग के कोच के रूप में दो साल का सफल कार्यकाल बिताया।

गुवाहाटी में भी होगा बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का मैच

एजेंसी । नई दिल्ली

पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट मेजबानी के बाद अब गुवाहाटी का बारसपारा स्टेडियम 2027 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के एक मैच की मेजबानी करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को पुरुष टीम के घरेलू सत्र का कैलेंडर जारी किया जिसमें पांच टेस्ट, नौ वनडे और आठ टी-20 मैच शामिल हैं। भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की नजरें वनडे मैचों पर रहेंगी क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की दिग्गज जोड़ी के उन सभी मैचों में खेलने की उम्मीद है। ये दोनों अब केवल वनडे खेलते हैं।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जनवरी, फरवरी और मार्च 2027 में खेली जाएगी। नागपुर, चेन्नई, रांची और अहमदाबाद को रोटेशन के अनुसार मेजबानी मिली है। पर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि गुवाहाटी को फिर से मेजबानी कैसे मिली जबकि वहा नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट हुआ था। साथ ही मुंबई और कोलकाता इस महत्वपूर्ण सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का कार्यक्रम

- पहला टेस्ट 21-25 जनवरी नागपुर
- दूसरा टेस्ट 29 जनवरी-2 फरवरी चेन्नई
- तीसरा टेस्ट 11 से 15 फरवरी गुवाहाटी
- चौथा टेस्ट 19 से 23 फरवरी रांची
- पांचवां 27 फरवरी से 3 मार्च अहमदाबाद

तीन और देश आएंगे

इसके अलावा भारत वेस्टइंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की मेजबानी भी करेगा। जिम्बाब्वे 2002 के बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय सीरीज खेलेगा। इस सत्र में 17 शहरों में 22 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे, जिनमें वेस्टइंडीज की टीम सबसे पहले भारत आएगी। उसका दौरा 27 सितंबर से शुरू होगा।

बॉ ली वु ड

अक्षय कुमार ने भाषा विवाद पर दी प्रतिक्रिया

अक्षय कुमार अपने बेबाक विचारों को लोगों के सामने रखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। आगामी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बॉलीवुड में भाषा विवाद पर अपना सीधा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने 1990 का वो दौर याद किया, जब फिल्मी सितारों के लिए अंग्रेजी को ₹फैशनेबल₹ माना जाता था। हालांकि अक्षय ने हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी और बड़े से बड़े पुरस्कार समारोह या वैश्विक समारोह में अपनी जड़ों को दृढ़ता के साथ बनाए रखा। हिंदी बोलने में सहजता महसूस करते हैं अक्षय कुमार बातचीत में, अक्षय ने अपनी भाषा की पसंद पर बात की। उन्हों कहा, ₹90 के दशक में, चाहे कोई पुरस्कार समारोह ही क्यों न हो, मैं हमेशा कहता था कि मैं हिंदी में बोलूंगा। आमतौर पर भी मैं हमेशा हिंदी में बोलता हूं। यहां तक कि मेरे कई सम्मेलनों में भी, जहां अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे कहता हूं, 'आप अंग्रेजी में बोलिए, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा।' यही मेरी सहजता है। अक्षय ने आगे बताया कि उनके लिए हिंदी हमेशा से प्रामाणिकता का प्रतीक रही है, धारणाओं की नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, 90 के दशक में बातचीत के लिए अंग्रेजी को व्यापक रूप से प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अक्षय और गोविंदा जैसे अभिनेता उन सितारों में से थे जिन्होंने हमेशा हिंदी को चुना। फिल्म 'भूत बंगला' की बात करें, तो इसमें तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और परेश रावल भी शामिल हैं। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित यह 10 अप्रैल को रिलीज होगी।

'एक दिन' का नया गाना 'ख्वाब देखूं' रिलीज

आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एक दिन' का नया रोमांटिक गाना 'ख्वाब देखूं' रिलीज हो गया है। ट्रेलर और टाइटल ट्रैक से पहले ही चर्चा में बनी इस फिल्म का यह गाना दर्शकों को एक सुकूनभरी प्रेम कहानी की दुनिया में ले जाता है। गाने में जुनैद खान और साई पल्लवी के बीच पनपते मासूम और प्योर रोमांस को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। शांत वादियों में फिल्माया गया यह गीत उनके रिश्ते के धीरे-धीरे गहराते एहसास को बखूबी दर्शाता है। इस गाने को अरिजीत सिंह और तरन्नुम मलिक जैन ने अपनी मधुर आवाज दी है। संगीत राम संपत का है, जबकि इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। गाने की धुन और लिरिक्स मिलकर एक रूहानी एहसास पैदा करते हैं, जो सीधे दिल को छू जाता है। 'एक दिन' खास इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए आमिर खान और फिल्ममेकर मंसूर खान लंबे समय बाद साथ काम कर रहे हैं। इस जोड़ी ने पहले 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर' और 'अकेले हम अकेले तुम' जैसी यादगार फिल्में दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है। फिल्म में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि निर्माण आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है और दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

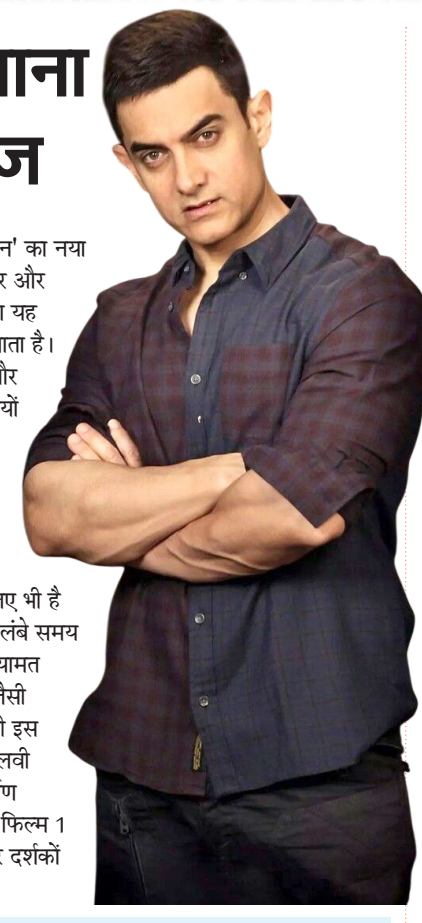

'वाल्मीकि रामायण' का भव्य ऐलान

पौराणिक महागाथा के सिनेमाई रूपांतरण वाल्मीकि रामायण की आधिकारिक घोषणा पोस्टर लॉन्च के साथ कर दी गई। इस भव्य थिएट्रिकल फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक भावना तलवार करेंगी। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ जुड़े हैं। प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल, लेखक और स्क्रीनराइटर आनंद नीलकंठन, सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान और पद्मश्री एवं ऑस्कर विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पूकुट्टी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इसके अलावा पद्मश्री सम्मानित चंद्रप्रकाश द्विवेदी को फिल्म का क्रिएटिव कंसल्टेंट बनाया गया है, जो कहानी की प्रामाणिकता और उसके स्वरूप की निगरानी करेंगे। निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल ग्रंथ पर आधारित एक सच्ची और निष्ठापूर्ण प्रस्तुति होगी। इसका उद्देश्य मूल कथा और उसके दार्शनिक पहलुओं को बिना बदलाव के उसी भाव में दर्शकों तक पहुंचाना है।

हालांकि 'वाल्मीकि रामायण' एक थिएट्रिकल फिल्म होगी, लेकिन इसमें आधुनिक फिल्म निर्माण तकनीकों, डिजिटल वर्कफ्लो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जाएगा, ताकि कहानी को भव्य और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

'ऑपरेशन सिंदूर' पर बनेगी फिल्म, विवेक अग्निहोत्री ने भूषण कुमार से मिलाया हाथ

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना की गई सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' अब बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज इस विषय पर फिल्म बनाने जा रही है, जिसने फिल्म जगत में उत्सुकता बढ़ा दी है। यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस 'टाइनी' ढिल्लों (सेवानिवृत्त) की किताब 'ऑपरेशन सिंदूरः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित होगी। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि यह कहानी समय की मांग है और इसे पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिल्म में बहादुरी, रणनीति और पेशेवर रवैये को प्रमुखता से दिखाया जाएगा, साथ ही इसे एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्माण टी-सीरीज और आईएम बुद्धा प्रोडक्शन के बैनर तले किया जाएगा। अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य शोर मचाना नहीं, बल्कि तथ्यों और स्पष्टता के साथ इस कहानी को सामने लाना है। फिलहाल फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बड़े राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

DBD
दो बजे दोपहर
मुंबई, शुक्रवार, 27 मार्च 2026

वॉर ब्रीफ

ईरान युद्ध में अमेरिका ने 10 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए

वाशिंगटन। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने बताया कि ईरान युद्ध में अब तक अमेरिकी सेना ने 10000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है।अमेरिकी नेवी के एडमिरल ब्रैड कूपर ने गुरुवार की सुबह सेंट्रल कमांड द्वारा जारी वीडियो में ये बातें कहीं।कूपर ने कहा, अगर आप हमारे द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को हमारे इजरायली सहयोगी की सफलताओं के साथ मिला दें, तो हमने मिलकर हजारों और ठिकानों पर हमला किया है। हमारे सटीक हमलों ने ईरान के हवाई सुरक्षा तंत्र को पस्त कर दिया है और हमारी लड़ाकू उड़ानें जमीन पर साफ असर दिखा रही हैं। ईरानी नौसेना के सबसे बड़े पोतों में से 92 प्रतिशत को नष्ट कर दिया है।

ईरान ने खार्ग द्वीप पर बिछाई बारूदी सुंरग

नई दिल्ली। ईरान ने अमेरिका की ओर से जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए खार्ग द्वीप पर बारूदी सुरंग बिछा दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका फारस की खाड़ी में जमीनी मौजूदगी बढ़ा रहा। कयास लगाया गया कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद ईरान ने दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए इलाके में बारूरी सुरंग बिछा दी है। ब्रिटेन के समाचार पत्र सीएनएन की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान ने द्वीप के आसपास एंटी-पर्सनल और एंटी-आर्मर माइंस सहित कई जाल बिछाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने ये कदम तब उठाया है जब उसे आशंका है कि अमेरिकी सैनिक द्वीप को निशाना बनाकर समुद्री हमला भी कर सकते हैं।

ईरान के साथ युद्ध वार्ता में शामिल होना चाहते हैं : गल्फ काउंसिल

रियाद। गल्फ देशों ने गुरुवार को कहा कि वे अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली किसी भी बातचीत में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि उन्हें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, फिर भी वे कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव जासेम अल-बुदैवी ने टीवी पर भाषण में कहा, हम इस संकट को सुलझाने के लिए होने वाली किसी भी बातचीत या समझौते में गल्फ देशों को शामिल करने की जरूरत पर जोर देते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिल सके।

गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ रहा युद्ध का असर : यूएन प्रमुख

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर सबसे गरीब और कमजोर आबादी पर पड़ रहा है। उन्होंने युद्ध को तुरंत खत्म करने और कूटनीति को फिर से बढ़ावा देने की अपील की। एक्स पर पोस्ट में, गुटेरेस ने कहा कि इस संघर्ष के मानवीय नतीजों को वे आम नागरिक भुगत रहे हैं जिनका इस संघर्ष में कोई हाथ नहीं है।उन्होंने कहा, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की लहरों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है।

पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी की 'इमरजेंसी' मीटिंग

- पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक
- राज्यों की तैयारियों की होगी समीक्षा

एजेंसी । नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार (27 मार्च 2026) को बुलाई गई यह मुख्यमंत्रियों की बैठक वैश्विक भू-राजनीतिक संकट और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की हलचल ने भारत के रसोई घर और ईंधन टैंक पर दबाव बढ़ा दिया है।

एलपीजी की कमी और घरेलू आपूर्ति

भारत वर्तमान में रसोई गैस की भारी कमी से जूझ रहा है। सप्लाई चैन टूटने से घरों तक सिलेंडर पहुँचने में देरी हो रही है। प्रधानमंत्री राज्यों से आग्रह करेंगे कि वे अपने स्तर पर ईंधन के भंडारण और वितरण को सुव्यवस्थित करें ताकि पैनिक न फैले।

'टीम इंडिया' की भावना और राज्यों का तालमेल

प्रधानमंत्री इस बैठक में संदेश देंगे कि यह संकट केवल केंद्र का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल से ही तेल की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित रखा जा सकता है। जिन राज्यों में आचार संहिता लागू है, वहां के मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि नीतिगत काम न रुके।

विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा

पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि युद्ध छिड़ता है, तो उन्हें सुरक्षित वापस लाना एक बड़ी चुनौती होगी। पीएम मोदी राज्यों से उन नागरिकों का डेटा और उनके परिवारों को सहायता देने की रूपरेखा पर बात कर सकते हैं, जैसा 'ऑपरेशन गंगा' या 'वंदे भारत' मिशन के दौरान हुआ था।

होर्मुज जलडमरूमध्य और भारत का 'वीटो'

दुनिया का एक-तिहाई गैस और तेल इसी संकीर्ण समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान ने अधिकांश देशों के लिए इसे बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर हाहाकार है। हालांकि, ईरान ने भारत को इससे अलग रखा है (यानी भारत के जहाजों को रास्ता मिल रहा है), लेकिन युद्ध की स्थिति में यह रियायत कभी भी खत्म हो सकती है। पीएम मोदी इसी संभावित 'कठिन समय' के लिए बैकअप प्लान पर चर्चा करेंगे।

आर्थिक स्थिरता और महंगाई पर लगाम

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर भारत में महंगाई पर पड़ता है। प्रधानमंत्री राज्यों को सतर्क करेंगे कि वे जमाखोरी (Hoarding) और अनावश्यक कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं,।

भारत के पास 60 दिन का ईंधन: सरकार

केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि देश में पेट्रोलियम और एलपीजी (एलपीजी) की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे 'भ्रामक और दुष्प्रचार' पर ध्यान न दें, जिसका उद्देश्य बेवजह घबराहट पैदा करना है।पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास कुल मिलाकर 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और भूमिगत रणनीतिक भंडारण (कवर्न) शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि मध्य पूर्व संकट के 27वें दिन भी देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा, हर भारतीय के लिए लगभग दो महीने की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध है, चाहे वैश्विक परिस्थितियां कैसी भी हों। साथ ही अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कुछ देशों में जहां ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि, राशनिंग, ऑड-ईवन नियम और पेट्रोल पंप बंद होने जैसी स्थिति है, वहीं भारत में ऐसी किसी भी आपातकालीन उपाय की जरूरत नहीं है।

पेट्रोल पंप मालिकों को राहत

सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ जगहों पर घबराहट में ईंधन खरीदने की घटनाएं सामने आईं, लेकिन सरकार ने इसे सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रामक वीडियो का परिणाम बताया। इसके बावजूद सभी उपभोक्ताओं को ईंधन उपलब्ध कराया गया और तेल कंपनियों ने रातभर डिपो चलाकर सप्लाई बढ़ाई। सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों को राहत देते हुए क्रेडिट सीमा 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दी है, ताकि कार्यशील पूंजी की कमी के कारण किसी भी पंप पर ईंधन की कमी न हो। मंत्रालय ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की मौजूदा स्थिति के बावजूद भारत को अपने 41 से अधिक वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल मिल रहा है।

एलपीजी आपूर्ति भी पूरी तरह सुरक्षित

एलपीजी को लेकर भी सरकार ने किसी तरह की कमी से इनकार किया है। मंत्रालय के अनुसार, घरेलू उत्पादन में 40% की वृद्धि की गई है, जिससे रोजाना उत्पादन 50 हजार मीट्रिक टन(टीएमटी) तक पहुंच गया है, जो कुल आवश्यकता का 60% से अधिक है। अब आयात की दैनिक जरूरत घटकर 30 टीएमटी रह गई है। इसके अलावा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से 800 टीएमटी एलपीजी की खेप पहले से रास्ते में है, जो देश के 22 आयात टर्मिनलों पर पहुंचेगी। सरकार ने कहा, लगभग एक महीने की एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित है और अतिरिक्त खरीद लगातार जारी है। तेल कंपनियां रोजाना 50 लाख से अधिक सिलिंडर की आपूर्ति कर रही हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए व्यावसायिक सिलिंडरों का आवंटन 50% तक बढ़ाया गया है।

'सीरियस हो जाओ, वरना पीछे हटने का रास्ता नहीं बचेगा'

- ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी
- 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव ईरान ने ठुकराया

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है। अमेरिका द्वारा शांति के लिए रखे गए 15-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान को 'अंतिम चेतावनी' देते हुए साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के वार्ताकारों को 'अजीब' बताते हुए कहा कि वे एक तरफ डील की भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सामने नाटक कर रहे हैं।

ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जल्द ही गंभीर हो जाओ, वरना इसके बाद जो होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।

ईरान का युद्ध जारी रखने का एलान

ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' ने स्पष्ट किया कि उन्हें अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं हैं। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि वे युद्ध तभी समाप्त करेंगे जब उनकी अपनी शर्तें पूरी होंगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने जोरदार हमले जारी रखेगा और किसी के दबाव में नहीं आएगा।

कुवैत एयरपोर्ट पर हमला और सैन्य तैनाती

शांति प्रस्ताव ठुकराने के तुरंत बाद ईरान ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। जवाब में अमेरिका ने क्षेत्र में अपने पैराट्रूपर्स और मरीन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इजरायल ने भी तेहरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिससे मामला पूरी तरह हाथ से निकलता दिख रहा है।

क्या था 15-सूत्रीय प्रस्ताव?

ईरान को प्रस्ताव सौंपने वाले पाकिस्तान के दो अधिकारियों ने 15 बातों का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें प्रतिबंधों में राहत, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना, मिसाइलों की सीमा तय करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना शामिल है। होर्मुज एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिसके माध्यम से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल का निर्यात होता है।

दहेज हत्या समाज पर कलंक : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या को समाज के लिए एक ₹गहरा कलंक₹ करार देते हुए पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों और महिला गरिमा के ऐसे गंभीर उल्लंघन के मामलों में अदालतों को जमानत देते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अपराध में जमानत देते समय 'न्यायिक विवेक' का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने केवल इस बात पर गौर किया कि आरोपी हिरासत में है, जबकि मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

डेढ़ साल की शादी और संदिग्ध हालात

कोर्ट ने इस तथ्य पर विशेष गौर किया कि महिला की शादी को मात्र डेढ़ साल हुए थे। कानून के मुताबिक, शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में हुई किसी भी संदिग्ध मौत को दहेज हत्या की श्रेणी में रखकर गहराई से जांचा जाता है। 1 सितंबर, 2024 को हुई इस घटना में सिर की चोट और सदमे (Shock) को मौत का कारण बताया गया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश को 'अनुचित' और 'कानून की नज़र में गलत' ठहराते हुए रद्द कर दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनी अहम गवाह

आरोपी पक्ष का दावा था कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने छठी मंज़िल से कूदकर 'आत्महत्या' की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस दलील को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में महिला के शरीर पर अंदरूनी और बाहरी, दोनों तरह की गंभीर चोटें पाई गई थीं, जो मौत से पहले हुए संघर्ष या हमले की ओर इशारा करती हैं। पीठ ने अपने फैसले में भावुक और सख्त लहजे में कहा कि दहेज प्रथा के कारण आज भी हज़ारों महिलाओं की जान जा रही है। लालच के चलते या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। कोर्ट ने इसे मानवाधिकारों का हनन और समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा बताया।

ब्रिटेन में राजनीतिक दलों को क्रिप्टो चंदे पर रोक

एजेंसी । लंदन

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने राजनीतिक पार्टियों को क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मिलने वाले चंदे पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि क्रिप्टो डोनेशन के जरिए अवैध और विदेशी धन आसानी से राजनीतिक व्यवस्था में आ सकता है। इससे लोकतंत्र को खतरा है।

इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए विदेश में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के चंदे पर सालाना एक लाख पाउंड की सीमा तय करने की घोषणा की। एक सरकारी रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई थी कि क्रिप्टो डोनेशन का सही आंकड़ा पता नहीं है और इसका इस्तेमाल विदेशी फंडिंग के लिए किया जा सकता है। हालांकि, रिफॉर्म यूके के नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी एक वैध निवेश और लेन-देन का तरीका है और सरकार उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना चाहती है।

ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक

एजेंसी । नई दिल्ली

नेशनल मेडिकल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद एक बड़ी एडवायजरी जारी की है। अब ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। 25 मार्च 2026 को जारी यह आदेश उन प्राइवेट क्लीनिकों पर स्ट्राइक है जो इस थेरेपी के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूल रहे थे। मेट्रो शहरों और टियर-2 शहरों में कई प्राइवेट क्लीनिक यह दावा कर रहे थे कि वे स्टेम सेल के जरिए ऑटिज्म को ठीक कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्पष्ट किया है कि इन बीमारियों के लिए यह थेरेपी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए अब इसे 'अवैध' श्रेणी में डाल दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट और आईसीएमआर का सख्त रुख

30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया था। इसके बाद ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव बहल ने NMC को पत्र लिखकर उन बीमारियों की सूची सौंपी जिन्हें मंजूरी मिली हुई है। कोर्ट का मानना है कि बिना मंजूरी के ऐसी थेरेपी देना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है।अब अगर कोई डॉक्टर या क्लीनिक ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल का विज्ञापन करता है या इलाज देता है, तो उसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और क्लीनिक को सील किया जा सकता है।

मिलावटी दूध से 16 मौतें

- एनएचआरसी ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली/पूर्वी गोदावरी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से मिलावटी दूध के कारण हुई मौतों का एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। फरवरी के मध्य से शुरू हुई इस त्रासदी ने अब तक 16 मासूमों और बुजुर्गों की जान ले ली है। जांच में पता चला है कि दूध में 'एथिलीन ग्लाइकोल' नामक एक बेहद ज़हरीला रसायन मिलाया गया था। यह आमतौर पर एंटी-फ्रीज़ के रूप में इस्तेमाल होता है। शरीर में जाने पर यह किडनी को पूरी तरह ठप कर देता है और 'मल्टी-ऑर्गन फेल्योर' (शरीर के कई अंगों का एक साथ काम बंद करना) की स्थिति पैदा कर देता है।

बीमारी के लक्षण और अस्पताल की स्थिति

फरवरी के मध्य से ही लोगों में पेट दर्द, उल्टी और पेशाब बंद होना (Anuria) जैसे लक्षण दिखने लगे थे। कई बुजुर्गों और बच्चों की किडलियों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें राजमहेंद्रवरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई मरीजों को बचाने के लिए तत्काल डायलिसिस की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी 16 लोग दम तोड़ चुके हैं।

खरगे ने महिला आरक्षण पर सरकार की जल्दबाजी पर उठाए सवाल

एजेंसी । नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने पूछा कि सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे ने यह भी दोहराया कि अप्रैल में विधानभा चुनाव खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने नारी वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधन के विचार पर कांग्रेस के साथ बैठक करने को कहा था। इसी के जवाब में खरगे का यह पत्र आया है।

पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा?

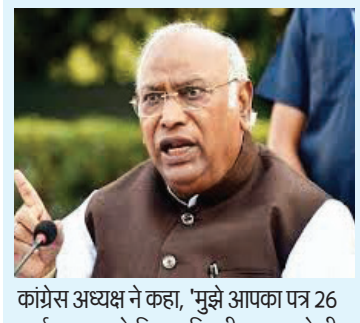

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'मुझे आपका पत्र 26 मार्च 2026 को मिला। विपक्षी दल पहले ही 24 मार्च 2026 को आपको पत्र लिख चुके हैं कि 29 अप्रैल 2026 के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के लागू करने पर चर्चा हो'। उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार तीस महीने बाद ही इस कानून में बदलाव को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। उन्होंने कहा, सभी नेता इस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए बैठक चुनाव के बाद ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे 2029 के लोकसभा चुनाव से इस कानून के लागू होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खरगे यह भी कहा कि 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने खुद इस कानून को तुरंत लागू करने की मांग की थी। लेकिन तब सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी।

एमयूडीए घोटाला

सिद्धरमैया की पत्नी को नोटिस

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एमयूडीए साइट (प्लॉट) आवंटन मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती बी. एम. को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने लोकायुक्त पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी बी-रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) पर जवाब मांगा है। अदालत ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में, आरोप लगाए गए थे कि सिद्धरमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में मुआवजे के तौर पर ऐसी साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन के स्थान की तुलना में कहीं अधिक था, जिसे एमयूडीए ने अधिग्रहित किया था।